वर्ष : 17 | अंक : 174 | मूल्य : 02 रुपया मात्र | पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित | मंगलवार 14 अप्रैल 2026 | लोकतंत्र का स्तंभ

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एकः पीएम

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का लागू होना 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यह अधिनियम न केवल महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भी नई मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, जो अतीत के सपनों को साकार करेगा और भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है और देश के विकास की यात्रा में महिलाओं की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मोदी ने बताया कि संसद के आगामी सत्र में इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाले विशेष सत्र के माध्यम से इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे पंचायत स्तर से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी को और आसान बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता दशकों से महसूस की जा रही थी। इस विषय पर लगभग चार दशक से विमर्श चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों और पीढ़ियों के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। वर्ष 2023 में जब यह अधिनियम संसद में पारित हुआ, तब सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी संवाद, सहयोग और सहभागिता के माध्यम से इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह सामूहिक प्रयास आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि आज देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री तक महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं और उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि देश में 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय निकायों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं और लगभग 21 राज्यों में पंचायतों में उनकी भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने इसे भारत के लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्हें एक ऐसी ग्राम पंचायत की महिलाओं से मिलने का अवसर मिला, जहां सभी सदस्य महिलाएं थीं।

महिला आरक्षण कानून से राष्ट्र निर्माण को नई दिशा मिलेगीः अन्नपूर्णा देवी

नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला आरक्षण कानून बनने से राष्ट्र निर्माण को नई दिशा मिलेगी। महिला सशक्तीकरण और राष्ट्र निर्माण को लेकर बड़ा संदेश दिया गया। अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार को विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए महिला आरक्षण अधिनियम को ऐतिहासिक और युगांतकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून मातृशक्ति के वर्षों के संघर्ष का परिणाम है, जो महिलाओं को लोकतांत्रिक भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में मजबूत स्थान देगा। उन्होंने कहा कि अब भारत महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर महिलाओं से विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं- जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा गया कि इनसे महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और नेतृत्व की भूमिका में आई हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाओं की विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, गणित (स्टेम) क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी, महिला पायलट्स की संख्या, स्टार्टअप्स में महिला नेतृत्व और पंचायतों में लाखों महिला प्रतिनिधियों को बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रही है। अब महिलाएं केवल परिवार ही नहीं, बल्कि देश की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। महिला आरक्षण अधिनियम उन्हें संसद और विधानसभाओं तक पहुंचाकर लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। उन्होंने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने में नारी शक्ति की भूमिका को निर्णायक बताते हुए सभी महिलाओं से इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

नेपाल के प्रधानमंत्री ने चौंकाया भारत को

महज 36 साल की उम्र में नेपाल के प्रधानमंत्री बने बालेन शाह ने शपथ लेते ही जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखाई है, उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उनकी भारत में हो रही है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में युवा लोगों को रखा है। नेपाल के पुराने धाकड़ राजनेता और राजवंश कहां चला गया, वह ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। बालेन शाह की कैबिनेट में शामिल सभी मंत्री उच्च शिक्षित और विशेषज्ञ हैं। मंत्रिमंडल की औसत आयु 38.21 वर्ष है। मंत्रिमंडल में 5 महिला मंत्रियों को स्थान दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री की कैबिनेट पूरी तरह से जेन-जी आंदोलन से निकलकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंची है। भारत सहित विश्व के अन्य देशों में जिस तरह से नेपाल सरकार की चर्चा हो रही है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है। उसकी प्रशंसा इन दिनों सारी दुनिया के जेन-जी में देखने को मिल रही है। नेपाल में पहली बार पारंपरिक राजनीति से हटकर युवाओं ने अपनी सरकार बनाई है।

सरकार को लेकर विशेषज्ञता और समर्पण को महत्व देते हुए जिस तरह से कार्य करना शुरू किया है, उससे आशा की एक नई किरण देखने को मिल रही है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भिजवा दिया। कठोर से कठोर निर्णय लेने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। विदेशों में नेताओं और अधिकारियों के जमा काले धन को नेपाल वापस लाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। बिना किसी लाग लपेट के प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्य नेपाल स्थित विभिन्न देशों के दूतावास पहुंच रहे हैं। जहां पर वह नेपाल के नए विकास मॉडल को लेकर विभिन्न देशों के राजदूतों से चर्चा कर रहे हैं। नेपाल की जरूरतों और विकास के लिए त्वरित निर्णय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री एक से एक बढ़कर एक हैं। कोई टेक्नोलॉजी से है, कोई पूर्व मेयर और संगीतकार रह चुका है। 2 मंत्री पीएचडी होल्डर हैं। वित्त मंत्री डा स्वर्णिम अर्थशास्त्र से पीएचडी कर चुकी हैं। विदेश मंत्री शिशर खनाल जिनकी उम्र 47 साल की है वह अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्नातक हैं।

नेपाल में पढ़े-लिखे लोगों का मंत्रिमंडल है। ऐसा मंत्रिमंडल दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यह बिल्कुल अलग है। सबसे अच्छी बात यह है, सारे युवा मिलकर नेपाल को नई दिशा देने के लिए अपना अधिक से अधिक समय दे रहे हैं। इनकी ऊर्जा देखने लायक है। जिस तरह से यह सोच समझकर गंभीरता के साथ निर्णय ले रहे हैं। निश्चित रूप से उसके सुखद परिणाम कुछ ही महीनो में दिखना शुरू हो जाएंगे। 2 सप्ताह पुरानी सरकार 100 सूत्री शासन सुधार एजेंडा पेश कर चुकी है। इस एजेंडे पर काम भी शुरू कर दिया है। मंत्रालयों का पुनर्गठन, दक्षिण एशिया संघर्ष के प्रभाव, नेपाल के एनआईआर की सुरक्षा का कार्य, कार्की आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही, संविधान संशोधन, पार्टी आधारित छात्र संघ व्यवस्था समाप्त करने, निजी अस्पतालों में 10 फीसदी मुफ्त बेड गरीबों के लिए। इस तरह स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए जिस तरह से सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, उसको देखते हुए, यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है, यदि यही उत्साह कुछ और समय तक बना रहता है तो आने वाले समय में नेपाल का भविष्य सारी दुनिया के लिए देखने योग्य होगा।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

बाबा खरात के 11 ठिकानों पर ईडी का छापा, हो सकता हैं बड़े नेटवर्क का खुलासा

नासिक। नासिक का फर्जी बाबा अशोक खरात मामले अब और गहराता जा रहा है, जिस शख्स पर लोगों को धोखा देने, दुष्कर्म और करोड़ों की ठगी के आरोप हैं, अब उसकी संपत्तियों पर ईडी की छापेमारी ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। 11 जगहों पर एक साथ छापेमारी ने साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ बाबा तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बड़ा नेटवर्क हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूछताछ में बाबा अशोक खरात बार-बार अजीब और गोलमोल जवाब देकर जांच एजेंसियों को उलझा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वह सच्चाई छिपा रहा है या सच में उसके सीने में बड़ा राज दफन है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की इस कार्रवाई ने मामले को सिर्फ आपराधिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक अपराध के दायरे में ला दिया है। बाबा खरात के घर, ऑफिस, फार्महाउस और मंदिर तक पर छापा मारा गया है जिससे पता चलता है कि जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं। इस बीच उसकी फरार पत्नी कल्पना खरात का रहस्य भी मामले को उलझा रहा है। पुलिस पिछले कई दिनों से उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।

गुजरात के सुरेंद्रनगर में सड़क हादसा, सात लोगों की मौत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जताया दुख

नई दिल्ली/गांधीनगर। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा जिले में लखतर–विरमगाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। लखतर पुलिस थाने के मुताबिक रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब डेढ़ बजे श्रद्धालुओं का एक समूह राजकोट से बहुचराजी माता मंदिर दर्शन के लिए पैदल जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं और सड़क किनारे खड़े एक डंपर चालक की मौत हो गई। मृतकों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सड़क हादसे में जानमाल के नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सुरेंद्रनगर में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक दुखद सड़क दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से मैं अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है।

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर रक्षा मंत्री ने दिया भरोसा, कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता तनाव गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन भारत संकट से सुरक्षित है। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय विदेश नीति और अन्य देशों के साथ मजबूत संबंधों को दिया। दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा रहा है और कई देशों में ईंधन की भारी किल्लत है, लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत यह है कि हमारे जहाज आज भी होर्मुज की खाड़ी से सुरक्षित गुजर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने उन तत्वों पर भी निशाना साधा जो तेल की कीमतों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने होर्डिंग और विज्ञापनों के जरिए दुष्प्रचार करने की कोशिश की, इन दावों को जनता ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और घरेलू अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के बारे में बात कर सिंह भावुक नजर आए। उन्होंने शहर के साथ अपने गहरे जुड़ाव का जिक्र कर कहा कि लखनऊ उनके दिल में बसता है। उन्होंने पिछले एक दशक में शहर के बुनियादी ढांचे में हुए बदलावों की सराहना की। इस विकास का श्रेय उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रशासन को दिया।

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सौ फीसदी एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की

एजेंसी। नई दिल्ली

पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की 100 फीसदी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जबकि देश में किसी भी एलपीजी वितरक के यहां स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पेट्रोल पंपों के पास ईंधन के पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे देश में एलपीजी की घरेलू आपूर्ति सामान्य है। उन्होंने कहा कि घरेलू ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडरों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की गई है, अभी घरेलू एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास घरेलू रसोई गैस की कमी (ड्राई-आउट) की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग का स्टेटस भी लगभग 99 फीसदी तक पहुंच गया है। इसके अलावा गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ओटीपी-आधारित एलपीजी डिलीवरी सिस्टम लागू किया गया है। सुजाता शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया में ओटीपी केवल ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाता है। इसलिए, अगर ग्राहक इस कोड को किसी और के साथ शेयर नहीं करता है तो यह सुरक्षित रहता है और कोई दूसरा व्यक्ति इसे एक्सेस नहीं कर सकता। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र के लिए न्यूनतम स्टॉक सीमा तय की है, जो 85 फीसदी से 90 फीसदी के बीच है। इस स्तर से ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूवल क्लीयरेंस (डीएसी) को बाईपास करने के लिए केवल राज्य प्रमुख या क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों से ही मंजूरी लेनी होगी। वहीं, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि अभी फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में भारतीय झंडे वाले किसी भी जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि भारतीय झंडे वाला एलपीजी जहाज 'जग विक्रम' 11 अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरा है। इस जहाज पर लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है और इसमें 24 नाविक सवार हैं।

एनएचए ने नवप्रवर्तकों को एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन के लिए किया आमंत्रित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने नवप्रवर्तकों, छात्रों, डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयोजित एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान की प्रक्रिया को अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए अभिनव डिजिटल समाधान विकसित करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को जारी बयान के अनुसार वर्तमान में योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 50,000 दावों का निपटान किया जाता है, जिनमें से केवल 15-20 प्रतिशत ही स्वतः (ऑटोमेटेड) रूप से निपटते हैं। बढ़ती दावों की संख्या और जटिलता को देखते हुए एक उन्नत, एआई-आधारित स्वचालित प्रणाली की आवश्यकता है, जो विभिन्न उपचार पैकेजों और दस्तावेज़ स्वरूपों को प्रभावी ढंग से संभाल सके। हैकाथॉन को देशभर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है और अब तक 2,600 से अधिक प्रतिभागी पंजीकरण कर चुके हैं। इच्छुक प्रतिभागी 13 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण का स्टालिन पर पलटवार, 'झूठा विमर्श' गढ़ने का आरोप

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन पर गेहूं और धान किसानों को दिए जाने वाले बोनस संबंधी केंद्र सरकार के परामर्श पर 'झूठा विमर्श' गढ़ने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। उन्होंने इससे संबंधित पत्र को सार्वजनिक कर स्टालिन को करारा जवाब दिया है। सीतारमण ने 'एक्स' हैंडल पर लिखा कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है, बल्कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक एडवाइजरी भेजी गई थी। यह सलाह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए थी, न कि किसानों के बोनस को रोकने के लिए था। उन्होंने कहा कि द्रमुक पार्टी इसके जरिए खुद को किसानों और तमिलनाडु के लोगों के रक्षक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। सीतारमण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक, निरंतर और सकारात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश के लिए यह स्थिति टिकाऊ नहीं है।

अब भारत में हो सकेगी अमेरिकी इंजन की मरम्मत, वायु सेना के साथ समझौता

एजेंसी। नई दिल्ली

वायु सेना को तेजस लड़ाकू विमान की आपूर्ति में हो रही देरी में तेजी से सुधार होगा

अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस भारतीय वायु सेना के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस फ्लीट को पावर देने वाले इंजन के लिए रिपेयर सेंटर बनाएगी। इस बावत अमेरिकन एयरक्राफ्ट इंजन आपूर्ति कंपनी ने सोमवार को वायु सेना के साथ समझौता किया है। देश में बनने वाली इस सुविधा का मालिकाना हक वायु सेना के पास होगा, जिससे विदेशी निर्भरता खत्म होने के साथ ही जरूरत पड़ने पर मरम्मत में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। एलसीए तेजस को जंग के लिए तैयार होने में तेजी लाने के मद्देनजर जीई एयरोस्पेस ने भारत में इंजन डिपो बनाने के लिए भारतीय वायु सेना के साथ समझौता किया है। अब एलसीए तेजस मार्क-1ए को पावर देने वाले एफ404-आईएन20 इंजन के लिए देश में ही रिपेयर और ओवरहॉल डिपो बनाया जायेगा। इससे वायु सेना को तेजस लड़ाकू विमान की आपूर्ति में हो रही देरी में तेजी से सुधार होगा, क्योंकि इससे मरम्मत के लिए विदेशी निर्भरता कम होगी और इंजन की रिपेयरिंग में लगने वाला समय भी बचेगा। यह सुविधा का निर्माण वायु सेना करेगी, लेकिन तकनीकी सहयोग जीई एयरोस्पेस देगी। कंपनी ने कहा कि डिपो का संचालन वायु सेना के हाथों में होगा, जिसमें जीई एयरोस्पेस प्रशिक्षित कर्मचारी, उन्हें प्रशिक्षण, जरूरी स्पेयर पाट्र्स और विशेष उपकरण की सप्लाई देगी। तेजस मार्क-1ए एयरक्राफ्ट के लिए एफ404-आईएन20 इंजन का नियमित तौर पर सालभर निर्माण करना लड़ाई की तैयारी के लिए जरूरी है, इसलिए आपूर्ति चेन में देरी से फ्लीट की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। भारत में ही रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधा सेट अप करने से लॉजिस्टिक दिक्कतों को कम करने में मदद मिलेगी।

इधर ईरान-अमेरिका लड़ते रहे, उधर चीन ने पीओके और अफगान सीमा के पास बना लिया प्रांत

एजेंसी। नई दिल्ली

एक ओर जहां पूरी दुनिया का ध्यान ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के खतरों पर टिका है, वहीं दूसरी ओर चीन ने भारत की सीमाओं के पास एक बेहद रणनीतिक और विवादास्पद कदम उठाया है। चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और अफगानिस्तान की सीमा के बेहद करीब स्थित अपने शिनजियांग प्रांत में एक पूरी नई प्रशासनिक इकाई यानी काउंटी स्थापित कर दी है। सेनलिंग नाम की यह नई काउंटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है, जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का यह कदम उइगर लड़ाकों की घुसपैठ को रोकने और वाखान गलियारे (वाखान कॉरिडोर) पर अपना नियंत्रण और सुरक्षा घेरा मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले एक साल के भीतर चीन द्वारा शिनजियांग में घोषित की गई यह तीसरी नई काउंटी है। इससे पहले वह हेआन और हेकांग नाम की दो अन्य प्रशासनिक इकाइयां बना चुका है। भारत ने पिछले साल ही इन जिलों के निर्माण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था, क्योंकि इन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और विवादित अक्साई चिन पठार के अंतर्गत आता है। भारत की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र की सरकार ने 26 मार्च को सेनलिंग की स्थापना की औपचारिक घोषणा की। यह नया जिला ऐतिहासिक शहर काशगर के प्रशासनिक नियंत्रण में आएगा। काशगर वही क्षेत्र है जहां से विवादास्पद चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू होता है और पीओके से होकर गुजरता है। इस नए जिले का गठन चीन की उस विस्तारवादी नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह अपनी सीमाओं पर नागरिक और सैन्य नियंत्रण को और अधिक पुख्ता करना चाहता है। रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, सेनलिंग जिला भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान के संकरे वाखान कॉरिडोर से जुड़ा है। यह 74 किलोमीटर लंबी पट्टी शिनजियांग को छूती है और ताजिकिस्तान व पीओके को अलग करती है।

संक्षिप्त समाचार

किसानों के लिए एमएसपी की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने किसानों को वाजिब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका पत्रकार और एक्टिविस्ट प्रकाश गोपालराव पोहरे की ओर से दायर की गई है। सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसी मांगे की गई हैं, जो देश की आर्थिक नीति को दोबारा लिखने जैसा है। हालांकि, बाद में कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य की दरें किसानों की लागत निकाल पाने के लिए भी नाकाफी साबित हो रही हैं, कृषि व्यवस्था दबाव में है और हर साल 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ट्रांजिट जमानत के फैसले को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुईयां सरमा के पास विभिन्न देशों के पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने के मामले में दर्ज एफआईआर में तेलंगाना उच्च न्यायालय की ओर से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली एक हफ्ते की ट्रांजिट जमानत के फैसले को असम सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक हफ्ते की ट्रांजिट रिमांड देने का आदेश दिया था। दरअसल, असम में एफआईआर दर्ज होने के बाद असम पुलिस ने 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के आवास पर छापा मारा था, लेकिन पवन खेड़ा अपने आवास पर नहीं मिले थे।

कांग्रेस ने लोकसभा सदस्यों को जारी किया व्हिप

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा के अपने सदस्यों को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि वे आगामी 16 से 18 अप्रैल तक होने वाली सदन की तीन दिवसीय विशेष बैठक में मौजूद रहें तथा पार्टी के रुख का समर्थन करें। कांग्रेस ने आधिकारिक बयान में कहा कि 16 से 18 अप्रैल तक लोकसभा में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार और मतदान होना है, इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए यह व्हिप उस वक्त जारी किया है जब सरकार संसद के मौजूदा बजट सत्र के तहत हो रही इस तीन दिवसीय बैठक में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने से संबंधित संशोधन एवं परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है।

सिंधिया मंगलवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय में डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां प्रधानमंत्री संग्रहालय में मंगलवार से चार दिवसीय एक विशेष डाक टिकट प्रदर्शनी "एक भारत, श्रेष्ठ भारतः डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र का उत्सव" का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) के मुताबिक यह प्रदर्शनी संचार मंत्रालय के डाक विभाग के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उद्घाटन समारोह 14 अप्रैल को दोपहर 12 प्रधानमंत्री संग्रहालय के ब्लॉक-I स्थित 'परिचय गैलरी' में होगा। यह प्रदर्शनी 17 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान भारत के संविधान, डॉ. बीआर आंबेडकर और 'भारत के लोग' विषयों पर आधारित विशेष 'पिक्चर पोस्टकार्ड' जारी किए जाएंगे। संग्रहालय ने देशभर से निजी डाक टिकट संग्राहकों को इस प्रदर्शनी में अपने संग्रह प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य डाक टिकटों के माध्यम से भारत की विकास यात्रा और उसके मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों को जनता के सामने लाना है। यह प्रदर्शनी स्वतंत्रता के बाद से जारी किए गए दुर्लभ और महत्वपूर्ण डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता, लोकतंत्र और सांस्कृतिक विविधता की यात्रा को प्रस्तुत करेगी। इसमें मुख्य रूप से कई विषयों को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति, भारतीय संविधान -लोकतांत्रिक संस्थाएं, स्वतंत्रता सेनानी-सांस्कृतिक विविधता और देशभर के निजी संग्रहकर्ताओं के दुर्लभ डाक टिकट शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान डाक विभाग और पीएमएमएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रदर्शनी का समापन 17 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 99वीं जयंती के अवसर पर होगा, जिसमें उन्हें समर्पित एक 'विशेष आवरण' जारी किया जाएगा। आगंतुकों, डाक टिकट संग्राहकों, विद्यार्थियों तथा आम जनता को डाक टिकट संग्रह की कला के माध्यम से इतिहास, विरासत और लोकतंत्र के इस अनूठे उत्सव का अनुभव प्राप्त होगा।

दिल्ली विधानसभा को फिर बम से उड़ाने की धमकी, साइनाइड गैस और आरडीएक्स का दावा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा को सोमवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में दावा किया गया है कि तीन घंटे के भीतर विधानसभा कार्यालय को साइनाइड गैस से भरे 15 आरडीएक्स बमों के जरिए उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और परिसर की सुरक्षा तुरंत कड़ी कर दी गई। जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 11:12 बजे विधानसभा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा संदेश भेजा गया। मेल में गंभीर दावा करते हुए कहा गया कि विधानसभा परिसर के भीतर विस्फोटक लगाए गए हैं, जो निर्धारित समय के भीतर धमाका करेंगे। ईमेल में यह भी लिखा गया कि केवल मुस्लिम कर्मचारियों को तत्काल वहां से हटा लिया जाए, जिससे मामले ने और संवेदनशील रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस तरह की धमकी पहली बार नहीं मिली है। इससे पहले 25 मार्च को भी इसी प्रकार का एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें दोपहर 1:40 बजे धमाका करने की बात कही गई थी। उस समय भी 15 आरडीएक्स आईईडी लगाए जाने का दावा किया गया था।

जैक्सन ग्रुप ने एनर्जी पोर्टफोलियों में बड़े विस्तार की घोषणा की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली : भारत के प्रमुख एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर समूहों में से एक जैक्सन ग्रुप ने अपने एनर्जी सॉल्यूशन में , पांच नए एनर्जी सॉल्यूशन पेश किए।वहीं,एनर्जी सॉल्यूशन पोर्टफोलियों में बड़े विस्तार की घोषणा की। इसमें पांच नए उत्साद शामिल हैं. जैकसन जेनसेट एक्स्ट्रा, बीईएसएस, सोलर किट, मोबाइल लाइट टावर (एमएलटी) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर। पोर्टफोलियो विस्तार "जैक्सन' की एक अधिक व्यापक और भविष्य के लिए तैयार एनर्जी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम। कंपनी की 78 वर्षों से अधिक की गौरवपूर्ण विरासत है। यह विरासत गुणवत्ता, भरोसे और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस से परिभाषित होती है। यह ग्रुप पावर जनरेशन, एनर्जी स्ट्रोरेज, सोलर को अपनाने और क्लीन पारंपरिक एनर्जी सॉल्यूशन में अपनी उपस्थिति को सशक्त कर रहा है। जैक्सन के चेयरमैन समीर गुप्ता ने कहा, "जैक्सन में हमारा मिशन हमेशा नवाचार के माध्यम से प्रगति को एनर्जी देना रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 ग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्म के साथ, जैक्सन के पास आज भविष्य के लिए तैयार एनर्जी सॉल्यूशन को आकार देने की क्षमता भी है। यह पोर्टफोलियो विस्तार एक एकीकृत एनर्जी इकोसिस्टम बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भरोसेमंद, जिम्मेदार और भारत तथा वैश्विक बाजारों में ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप है।" जैक्सन के वाइस चेयरमैन संदीप गुप्ता ने कहा, बाजार ऐसे एनर्जी सॉल्यूशन की तलाश में है, जो दक्ष, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार हों। इस विस्तारित पोर्टफोलियो के साथ, जैक्सन विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने वाले एक विविधीकृत खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है।" जैक्सन डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी बिजनेस के सीईओ सुधांशु पोखरियाल ने कहा, "यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम अपने पोर्टफोलियो का विस्तार ऐसे समाधानों के साथ कर रहे हैं, जो विश्वसनीयता और स्थिरता का संयोजन हैं और ग्राहकों को उनकी ऊर्जा जरूरतों को अधिक विश्वास और लचीलेपन के साथ पूरा करने में मदद करते हैं।"उन्होंने कहा,पोर्टफोलियो विस्तार "जैक्सन' की एक अधिक व्यापक और भविष्य के लिए तैयार एनर्जी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम। कंपनी की 78 वर्षों से अधिक की गौरवपूर्ण विरासत है। "

हुसैनी टाइगर्स इटावा के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, शोक पत्र सौंपा

लोकतंत्र की शान

इटावा। सामाजिक एवं सामुदायिक एकता के लिए कार्यरत संगठन हुसैनी टाइगर्स इटावा के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही से मुलाकात की। इस दौरान संगठन की ओर से गहरा शोक व्यक्त करते हुए एक संवेदना पत्र (कंडोलेंस लेटर) भी सौंपा गया। जानकारी के अनुसार, हुसैनी टाइगर्स के जिला अध्यक्ष मोनू मंसूरी की अनुपस्थिति में उनके पुत्र गुलाम हुसैन वारिस ने संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए यह पत्र सौंपा। वहीं संगठन के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम वारिस ने भी अपनी ओर से शोक पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में अनवर अंसारी, मेहताब अंसारी और मोहम्मद इमरान भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर दुख की इस घड़ी में एकजुटता और संवेदना व्यक्त की तथा शांति, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह मुलाकात संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण रहा, जिसमें उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इंसानियत और सहयोग का संदेश आगे बढ़ाया।

उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू सर गंगा राम अस्पताल के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू सोमवार को सर गंगा राम अस्पताल के 71वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य और भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। सर गंगा राम अस्पताल के 71वें स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल ने कहा कि सर गंगा राम एक महान इंजीनियर और दूरदर्शी परोपकारी व्यक्ति थे जिनकी विरासत सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनी हुई है। 'गुरु का बाग मोर्चा' आंदोलन के साहसी समर्थन से लेकर देखभाल के स्थायी संस्थानों के निर्माण तक उनका जीवन "सेवा" का एक प्रमाण था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरेगा, खासकर तब जब दुनिया के कई विकसित देश तेजी से वृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके विपरीत भारत एक युवा देश है, जहां औसत आयु लगभग 28 वर्ष है और 50 प्रतिशत से अधिक आबादी इससे कम उम्र की है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि सर गंगाराम का पंजाब के साथ बहुत संबंध है और मेरे परिवार के साथ बहुत सहयोग है। मेरे बेटे का जन्म भी इसी अस्पताल में हुआ था। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। भारत सबसे युवा देशों में से एक है इसलिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उसके स्वास्थ्य कर्मचारी कुशल हों। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन 'वैश्विक भलाई के लिए युवा' का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि यह संस्थान प्रधानमंत्री के अनुरूप, सुलभ और समावेशी स्वास्थ्य सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ नैदानिक उत्कृष्टता को संतुलित करके उनके मूल्यों को कायम रख रहा है। यदि भारत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करता है और स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल में सुधार करता है, तो यह वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकता है। संधू ने कहा कि केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल-आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया में उम्रदराज आबादी बढ़ेगी, सहायक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ेगी।उन्होंने सर गंगा राम अस्पताल की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने और कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

महिला आरक्षण की आड़ में गलत परिसीमन करना और जातिगत जनगणना से बचना चाहती है मोदी सरकार- कांग्रेस

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली: कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण के पीछे छुपकर 'शकुनी चाल' चल रही है, ताकि वह देश में गलत परिसीमन कर सके और उसे जातिगत जनगणना न करानी पड़े। कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख का हवाला देते हुए कहा कि परिसीमन के जरिए छोटे और परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले राज्यों को पूर्ण या तुलनात्मक रूप से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार जनगणना के आंकड़ों के बिना जो परिसीमन करने जा रही है, वह गलत तरीका होने के साथ-साथ खतरनाक है। इससे उत्तर-दक्षिण राज्यों के बीच विभाजन भी पैदा होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन का मतलब सिर्फ सीटें बढ़ाना नहीं है, बल्कि न्यायसंगत प्रतिनिधित्व देना है। उन्होंने कहा कि 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और फिर 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन यह पांच साल पीछे चल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना जनगणना के आंकड़ों के परिसीमन कैसे किया जा सकता है? जिन-जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, वहां लाखों-करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं, यानी सरकार मान रही है कि अलग-अलग जगहों पर जनसंख्या के आंकड़े बदल रहे हैं। ऐसे में किस आधार पर परिसीमन किया जाएगा? सरकार कैसे फैसला लेगी कि एससी-एसटी आरक्षित सीटें कौन सी होंगी? उन्होंने पूछा कि जनगणना के पूरे आंकड़े अगले साल 2027 तक उपलब्ध हो जाएंगे, तो सरकार तब तक इंतज़ार क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बिहार और तेलंगाना में हुए जातिगत सर्वे बताते हैं कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितनी अधिक है और इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी ने 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित होते समय कहा था कि ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन जातिगत जनगणना कराने और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने से बचने के लिए मोदी सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कर रही है।

जामिया इस्लामिया दिल्ली संस्था के प्रतिनिधी मंडल ने डा.अब्दुल मजीद हकीम इलाही को शोक पत्र सोंपा

लोकतंत्र की शान

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामना ई के चेहलुम के अवसर पर जामिया इस्लामिया दिल्ली संस्था के दिल्ली प्रदेष अध्यक्ष मो. रियाज़ ने प्रतिनिधी मंडल के साथ नई दिल्ली में स्थित ईरान कल्चरल हाउस में आयतुल्ला खामना ई के प्रतिनिधी डा. अब्दुल मजीद हकीम इलाही से भेंट करके आयतुल्लाह ख़ामना ई की षहादत पर षोक व्यक्त करते हुए संस्था की ओर से उन्हें षोक पत्र दिया। इस अवसर पर मो. रियाज़ ने कहा भारत ही नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों को ख़ामना ई की मृत्यु पर दुख व अफसोस है हम सब दुआ करते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांती दे और उन्हें स्वर्ग में शीर्ष स्थान मिले। मरहूम ने अपने पूरे जीवन में दुनिया को शांती, न्याय और एकता का संदेश दिया। उन्होंने मानवता के लिए सारी ज़िन्दगी सेवा की जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आयतुल्लाह ख़ामना ई की संरक्षता में भारत और ईरान के संबंध बेहतर रहे यही कारण है उनकी मृत्यु पर भारत के सेक्युलर लोग रोज़ाना राजधानी दिल्ली में स्थित ईरान कल्चरल हाउस में संवेदना के लिए बराबर आ रहे हैं। जामिया इस्लामिया संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. मो. एजाज़ ने कहा आयतुल्लाह ख़ामना ई की अध्यक्षता में ईरान ने तरक्की का सफर शून्य से शुरू करके तरक्की के शिखर तक पहुंचाया जिसका लोहा मार्च 2026 की ईरान, अमरीका , इज़राईल के युद्ध में दुनिया मान चुकी है। ईरान ने इस युद्ध में सच्चाई का साथ देकर झूठ को पराजित किया। क़ारी मो. यासीन ने कहा आयतुल्लाह ख़ामना ई दुश्मन ताक़तो के आगे कभी झुके नहीं उन्होंने सदैव इस्लाम शत्रु देशों का बेख़ौफ और निडर होकर मुकाबला किया है, वो अधिकार और न्याय की जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने आखिरी समय तक इस्लाम का झंडा मज़बूती से पकड़ा, वो भारत को हमेशा बेहतर पड़ौसी मानकर महत्व देते थे यहीं कारण है उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर विश्व स्तर पर भारत का समर्थन किया था। चेहलुम सभा में डा.अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने आयतुल्लाह ख़ामना ई के जीवन पर रौशनी डालते हुए बताया ख़ामना ई ने ईरान के सुप्रीम लीडर होने के बावजूद बहुत सादा जीवन व्यतीत किया जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है ना उनका और ना उनके चारों पुत्रों का अपना कोई निजी मकान नहीं है। प्रतिनिधी मंडल में उपस्थित सदस्यः मो. मुजाहिद खान, तारिक़ परवेज़, मो. अनवर, मो. आदिल, मो. नासिर, मो. ज़ाहिद इत्यादी।

कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ खड़ी, हम डरेंगे नहीं: राहुल गांधी

नव दर्पण

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां पर लगाए गए आरोपों के बाद दर्ज हुई एफआईआर मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि सरमा अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए अपनी मुख्यमंत्री की सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर जो आरोप लगाए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार संचालन में पारदर्शिता की वकालत करते हुए कहा कि पारदर्शिता, सत्ता की जवाबदेही और कानून का राज संवैधानिक मूल्यों का आधार है। मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ खड़ी है।उल्लेखनीय है कि 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां पर संयुक्त अरब अमीरात, एंटीगुआ-बरमूडा और मिस्र समेत तीन अलग-अलग देशों के चालू पासपोर्ट रखने और अमेरिका के वायोमिंग और यूएई में बिना चुनाव आयोग को बताए करोड़ों की संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। हालांकि सरमा ने इन दावों को दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया था और 48 घंटे के भीतर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद रिंकी भुइयां की एफआईआर पर असम पुलिस ने 7 अप्रैल को पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर छापा मारा था।

एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में, घबराहट में न आएं दिल्लीवासी: मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि राजधानी में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर, पर्याप्त और नियंत्रण में है। दिल्ली में एलपीजी या किसी भी अन्य ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आएं और संयम बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने एक बयान में घरेलू रसोई गैस की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि 12 अप्रैल को 1,11,766 बुकिंग दर्ज की गईं, जबकि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने मिलकर 1,30,094 सिलेंडरों की डिलीवरी की, जो बुकिंग से काफी अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लंबित बुकिंग्स को तेजी से निपटाया जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनी हुई है। वर्तमान में औसत डिलीवरी समय 3.87 दिन है, जो पहले के 4.24 दिनों से घटकर कम हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली को प्रतिदिन 6,480 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का आवंटन किया गया है। इसके मुकाबले पिछले एक सप्ताह में औसत दैनिक खपत केवल 4,268 सिलेंडर रही है, जिसमें पांच किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की खपत भी शामिल है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान में उपलब्धता मांग से अधिक है। मुख्यमंत्री ने सभी कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं, विशेषकर पांच किलोग्राम सिलेंडर उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक चिंता या भंडारण से बचें। पूरे शहर में वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य कर रही है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अगर किसी कमर्शियल उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो वे दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रण कक्ष से 011-23379836 या 8383824659 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं और संस्थानों को यह भी प्रोत्साहित किया है कि जहां भी पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, वहां इसका उपयोग करें क्योंकि यह एक विश्वसनीय और निरंतर ईंधन आपूर्ति प्रदान करता है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे बड़े उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र पीएनजी अपनाने की सलाह दी गई है, जिससे दक्षता, सुरक्षा और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को मध्यम और दीर्घकालिक समाधान के रूप में इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकिंग अपनाने के विकल्प पर भी विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार स्थिति पर प्रतिदिन करीबी नजर बनाए हुए है और राजधानी में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

निवेश के नाम पर 45.90 लाख की ठगी का खुलासा, केरल से आरोपित गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। निवेश के नाम पर 45.90 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपित को केरल से गिरफ्तार किया है। आरोपित को केरल के कोंडोट्टी इलाके से दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान कलंगोट्टिल, वलियापरंबा जिला मलप्पुरम (केरल) निवासी जमशीद के (33) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के बैंक खाते में ठगी की रकम का करीब 10 लाख रुपये ट्रेस हुआ, जिसे बाद में अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह से जुड़ा हुआ है और उसका मुख्य मकसद लोगों को ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर मोटी रकम ठगना था। आरोपित और उसके साथियों द्वारा बैंक खातों को किराए पर देकर ठगी की रकम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था, ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने सोमवार को बताया कि यह मामला एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता संदीप कुमार को फेसबुक के माध्यम से एक ट्रेडिंग कंपनी का लिंक भेजा गया था। इसके बाद उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर "इंडियन निवेश" नामक एप डाउनलोड कराया गया। आरोपितों ने उसे शेयर बाजार में निवेश कर भारी मुनाफे का लालच दिया, जिसके झांसे में आकर उसने अलग-अलग 8 बैंक खातों में कुल 45.90 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद एप में करीब 7 करोड़ रुपये का फर्जी मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो उससे और रकम जमा करने को कहा गया। मना करने पर उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया और आरोपी फरार हो गए। मामले में एफआईआर संख्या 43/25 धारा 318(4) बीएनएस के तहत क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज की गई। इसके बाद जांच क्राइम ब्रांच की डब्ल्यूआर-2 टीम को सौंपी गई। जांच के दौरान बैंक खातों का विश्लेषण करने पर पता चला कि ठगी की रकम का बड़ा हिस्सा केरल के एक एक्सिस बैंक खाते में गया है, जो जेएफएस ट्रेडर्स के नाम पर था। समन्वय पोर्टल की जांच में इस खाते से जुड़ी 21 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें भी सामने आईं। इसके बाद इंस्पेक्टर अक्षय के नेतृत्व में टीम गठित कर केरल भेजा गया। तकनीकी और मैन्युअल सर्विलांस के आधार पर पांच अप्रैल 2026 को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

संक्षिप्त समाचार

चेयरमेन राजपाल सैनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के संग अंबेडकर पार्क पर मनाया दीपउत्सव

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर हसनपुर आदर्श नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राज्यपाल सैनी ने भाजपा हाई कमान के आदेश पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर पार्क पर पहुंचकर दीप उत्सव मनाया तथा मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क के चारों ओर मामबत्तियां जलाकर दीप उत्सव मनाया, इस मौके पर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने बताया कि नगर पालिका द्वारा अंबेडकर पार्क पर विशेष सफाई व्यवस्था एवं रंग बिरंगी लाइटों की विशेष व्यवस्था की गई है तथा हाई कमान के आदेश पर अंबेडकर पार्क पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जयंती के की पूर्व संध्या पर अंबेडकर पार्क पर दीप उत्सव मनाते हुए चारों ओर दीप प्रज्वलित किए गए हैं इस मौके पर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम, सभासद शुभम अग्रवाल, पंकज भटनागर, राजपाल सैनी, सचिन गुप्ता, अर्पण गुप्ता, रविशंकर शर्मा, जगबीर मौर्य, रामवीर सिंह, अरविंद अन्ना, रितेश कुमार, जंग बहादुर, राहुल, अशोक, विक्रांत शर्मा आदि मौजूद रहे।

भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि के जिला अध्यक्ष ने अंबेडकर पार्क पर जलाए दीप

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुर/कालाखेड़ाः सोमवार को भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि के जिला अध्यक्ष शमशेर अली सैफी ने डॉ भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर न्याय पंचायत कालखेड़ा में स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया अंबेडकर पार्क पर दीप प्रज्वलित कर नमन किया, उन्होंने कहा कि आज हम बाबा साहब के संविधान के कारण खुले आसमान में सांस ले रहे हैं बाबा साहब की शिक्षाओं को हमें जीवन में उतरना चाहिए, इस मौके पर सुधीर चौहान, डॉक्टर मिंटू सागर, महेंद्र सिंह, नन्हे सिंह, रामवीर सिंह, तुलाराम सिंह, प्रकाश शेर सिंह, नेतराम, राजपाल सिंह, विकास, मास्टर सतपाल सिंह, रामकुंवर, प्रकाश गौतम आदि सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जिला कार्यकारिणी स्काउटस एंड गाईडस की बैठक

लोकतंत्र की शान : अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ , महमूदाबाद, सीतापुरः भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उप्र की सीतापुर जिला कार्यकारिणी और स्काउटर्स और गाइडर्स की बैठक मां संकटा देवी धाम महमूदाबाद में सम्पन्न हुई। बैठक में नये शैक्षिक सत्र की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी। बैठक में संकल्प किया गया कि स्काउट्स और गाइड्स के नियमों और प्रतिज्ञाओं को जीवन के कार्य व्यवहार में उतारने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। जनपद बाराबंकी के जिला मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंड गाइड डॉ. रामकुमार गिरि ने विस्तार से स्काउट्स और गाइड्स के उद्देश्य पर चर्चा की। डीटीसी मदन मोहन त्रिवेदी, डीओसी स्काउट नीरज पाण्डेय, दीपक कुमार, जिला कमिश्नर रूपेश अवस्थी, जिला गाइड कमिश्नर दीप्ति मिश्रा, कोषाध्यक्ष रईस अहमद, जिला स्काउट मास्टर आशीष पाण्डेय, जिला सचिव ऋषि मिश्र ने कार्ययोजना रखी। इस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। बैठक की अध्यक्षता सीतापुर जिला मुख्यायुक्त आरके वाजपेयी 'विरल' ने की। बैठक को मुख्यालय आयुक्त पंकज पाण्डेय, डॉ. देवेन्द्र पाण्डेय, अनिल वंशवार, अवधेश नन्दन अवस्थी, मनोज यादव, बृजेन्द्र सिंह, संजय कुमार, परवीन बानो, प्राची वाजपेयी, रामबाबू सत्यार्थी, प्रतिभा सिंह, प्रतिभा यादव, पुष्पा आर्या, अपर्णा मिश्रा नें सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव ऋषि कुमार मिश्र ने किया। आभार प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यायुक्त आरके वाजपेयी 'विरल' ने सभी से कार्ययोजना को अमली जामा पहनाने की अपील की। बैठक का शुभारम्भ स्काउट प्रार्थना और समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

चेयरमैन कौसर अब्बास ने किया स्टेशन रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

लोकतंत्र की शान : संभल/सिरसी। नगर पंचायत सिरसी के अंतर्गत स्टेशन रोड पर चल रहे निर्माण कार्य का आज चेयरमैन कौसर अब्बास द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का बारीकी से जायजा लिया गया। इस दौरान चेयरमैन ने मोहल्ला वासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। स्थानीय लोगों द्वारा रखी गई समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। चेयरमैन कौसर अब्बास ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर पंचायत का उद्देश्य प्रत्येक वार्ड में बुनियादी सुविधाएं समय पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराना है, जिससे क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

संभलः अंबेडकर जयंती को लेकर थाना हज़रत नगर गढ़ी में पीस कमेटी की बैठक संपन्न

लोकतंत्र की शान : संवाददाताः सैय्यद कुमैल ज़ैदी, संभल। डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती (14 अप्रैल) के उपलक्ष्य में थाना हज़रत नगर गढ़ी परिसर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एक महत्वपूर्ण पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्राधिकारी (सीओ) आईपीएस आलोक कुमार भाटी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर पवार ने क्षेत्र के गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए अपील की कि अंबेडकर जयंती के सभी कार्यक्रम परंपरागत, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी नया कार्य या नई परंपरा शुरू न की जाए, बल्कि जो कार्यक्रम वर्षों से चलते आ रहे हैं, उन्हें उसी तरह मनाया जाए। बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम आयोजित न किया जाए और सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों ने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए इस पावन अवसर को गरिमामय बनाया जाए। बैठक में सिरसी कौसर अब्बास चेयरमैन नगर पंचायत सिरसी, देवेंद्र सिंह फौजी, उमेश सागर ग्राम प्रधान पोटा, दानिश ग़दीरी, शहरोज़ पाशा, पप्पू सहित थाना क्षेत्र के सम्मानित नागरिक मौजूद रहे और प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

भाजपाईयों ने अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर पार्क पर जलाये 1100 दीप

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः सोमवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हसनपुर मंडल अध्यक्ष राजू राणा के नेतृत्व में मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी की गरिमामई उपस्थिति में नगर के अंबेडकर पार्क पर 1100 दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब को नमन किया, बताते चलें कि अंबेडकर जयंती से पूर्व ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सर्वप्रथम अंबेडकर पार्क पर पहुंचकर विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी एवं राजू राणा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क की सफाई की तथा शाम ढलते ही हसनपुर मंडल अध्यक्ष राजू राणा के नेतृत्व में तथा मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर पार्क को 1100 दीपो से रोशन किया, इस संबंध में विधायक महेंद्र सिंह ने बताया कि बीजेपी हाई कमान के आदेश पर पूरे देश में बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित किये जा रहे हैं, इसी क्रम में हसनपुर स्थित अंबेडकर पार्क पर भी अंबेडकर पार्क को 1100 दीपों से रोशन किया गया है, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आज दीपावली है,तथा विधायक ने सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी, इस अवसर पर मुख्य रूप से हसनपुर मंडल अध्यक्ष राजू राणा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शिखर अग्रवाल, पोरुष अग्रवाल, देवेंद्र खड़कवंशी, संजय शर्मा, अतुल गर्ग, अंकुर अग्रवाल, पवन राज जाटव, अजय पॉल, पंकज भटनागर, गजराज सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एआईएमआईएम पार्टी की हसनपुर विधानसभा का हुआ विस्तार सौपी गई जिम्मेदारी

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर : सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की एक बैठक पार्टी के हसनपुर विधानसभा अध्यक्ष छुन्नन अल्वी की अध्यक्षता में नगर के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर आयोजित की गई जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव हाजी शहजाद खान मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में हसनपुर विधानसभा का विस्तार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए आदिल मलिक को विधानसभा उपाध्यक्ष, शाहिद अंसारी को विधानसभा को महासचिव, दिलशाद चौधरी को विधानसभा महासचिव, कदीर कुरैशी को विधानसभा महासचिव, रऊफ सलमानी वह अयूब सलमानी को विधानसभा संयुक्त सचिव, असलम खा को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया तथा सभी को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारी से पार्टी हित एवं जनहित में कार्य करने तथा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आवाहन किया, इस मौके पर बैठक में मुख्य रूप से हाजी आसिफ, डॉक्टर वेकार चौधरी, गुड्डू, जफर, शहज़ेब सलमानी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने की भावनात्मक अपील- परिवार सबसे बड़ी पूंजी, मिल-बैठकर हल करें पारिवारिक समस्याएं

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदैव कहते हैं कि 25 करोड़ प्रदेशवासी ही मेरा परिवार है। सोमवार को उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में इसे चरितार्थ भी किया। 'जनता दर्शन' में आए प्रत्येक नागरिक से उन्होंने स्वयं मुलाकात की। सभी की शिकायतें सुनीं और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश भी दिए। इस दौरान कई शिकायतें पारिवारिक विवाद से जुड़ी आईं, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी को समझाया और कहा कि परिवार सबसे बड़ी पूंजी होती है। समझदारी से पारिवारिक मामले मिल-बैठकर सुलझाएं। विश्वास करिए, बिखरने के बजाय परिवार एकजुट हो जाएगा और वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी भी एक रहेगी।

अंतिम विकल्प में लें पुलिस-प्रशासन की मदद-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारिवारिक विवादों से जुड़ी सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना। फिर शिकायत लेकर आए लोगों ने कहा कि पारिवारिक झगड़ों में पुलिस-प्रशासन की सहायता लेना अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। हमारे समाज में परिवार से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। श्रेयस्कर यही है कि घर के मामले घर में ही सुलझ जाएं। गलती परिवार के किसी भी सदस्य से हो सकती है, लेकिन थोड़ा समझदारी से काम लेंगे तो परिवार बिखरने से बच जाएगा। परिवार में थोड़ा झुकने से सम्मान कम नहीं होता। परिवार रूपी पूंजी को हर हाल में संभाल कर रखें। कोई भी दिक्कत है तो परिवार के बड़ों के साथ मिल-बैठकर हल करें। यदि किन्हीं कारणों से विवाद हल नहीं होता तो अंतिम विकल्प के रूप में शासन, प्रशासन या पुलिस की सहायता लें।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जनभवन के 5.17 करोड़ रुपये से निर्मित नवीन भवन का किया उद्घाटन

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जनभवन के 5.17 करोड़ रुपये से निर्मित नवीन भवन का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने इस अभिनव प्रयास के लिए राज्यपाल का आभार प्रकट किया। उन्होंने बच्चों को सीख दी कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। प्रयास करने से सभी कार्य होते हैं। परिश्रमी व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होता है। इस अवसर पर अतिथियों ने 'हमारा जनभवन' पुस्तक का विमोचन भी किया और विद्यालय की प्रधानाचार्या व चालक को स्कूल बस की चाबी प्रदान की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः।। अर्थात कोई भी अयोग्य नहीं है। जैसे कोई अक्षर अयोग्य नहीं है, हर अक्षर में मंत्र और हर वनस्पति में औषधि बनने की ताकत है। वैसे ही हर मनुष्य में योग्य बनने का सामर्थ्य है, लेकिन उसके लिए योजक चाहिए। शिक्षा के लिए राज्यपाल ने योजक के रूप में मॉडल प्रस्तुत किया है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा परिषद इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं। यह उदाहरण हर एक क्षेत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है।

सीएम ने बच्चों को दिया वैद्य जीवक का उदाहरण-सीएम योगी ने बच्चों के समक्ष वैद्य जीवक का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने आयुर्वेद में पहचान बनाई। तक्षशिला में शिक्षा अर्जित करने के बाद गुरु से आज्ञा लेने गए और कहा कि मैं वापस अपने देश-घर जाना चाहता हूं। इस पर गुरु ने कहा कि पहले परीक्षा देनी होगी। वन में जाओ और ऐसी वनस्पति ढूंढकर लाओ, जिसमें औषधीय गुण न हो। जीवक ने तक्षशिला के वन में जाकर कई दिनों तक निवास किया और वापस आकर गुरु से कहा कि ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है, जिसमें औषधीय गुण न हो।

मदीने की याद में छलके अकीदत के आंसूः होटल सिल्वेट में शारिक अल्वी की रूहानी तकरीर ने आज़मीन को किया अश्कबार

» **हिना ट्रैवल सर्विस, रियाज टूर एंड ट्रैवल और शान एंटरप्राइजेज का हज प्रशिक्षण समारोह**

लोकतंत्र की शान अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ

लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल सिल्वेट में आज उस वक्त एक अज़ीम-उल-शान और रूहानी मंजर देखने को मिला, जब 'लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक' की सदाओं के बीच हज 2026 के मुकद्दस सफर की तरबियत का आगाज़ हुआ। हिना ट्रैवल सर्विस, रियाज टूर एंड ट्रैवल और शान एंटरप्राइजेज के मुश्तरका (संयुक्त) जेर-ए-एहतेमाम आयोजित इस प्रोग्राम में आज़मीन-ए-हज का जोश-ओ-खरोश और उनकी आंखों में दीदार-ए-इलाही की तड़प साफ नजर आ रही थी। कार्यक्रम के मुख्य केंद्र और देश के विख्यात मास्टर हज ट्रेनर शारिक मुख्तार अल्वी "शारिक अल्वी" ने जब अपनी मखसूस पुर-असर और जज्बाती आवाज में गुफ्तगू का आगाज़ किया, तो पूरे हॉल में एक वजीदानी कैफियत (रूहानी सन्नाटा) छा गई। शारिक अल्वी ने जब इंतहाई दर्द-ओ-मोहब्बत के साथ मक्का मुकर्रमा की अजमत और मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस गलियों का जिक्र छेड़ा, तो आज़मीन के दिलों के तार बज उठे। उन्होंने जब मुसाफिरान-ए-हरम को संबोधित करते हुए कहा कि "जब आप गुम्बद-ए-खजरा के सामने खड़े होकर आका-ए-दो आलम (सल्ल.) को अपना सलाम पेश करेंगे, तो वह पल आपकी पूरी जिंदगी की बंदगी का हासिल होगा," तो वहां मौजूद आज़मीन अपने जज्बात पर काबू न रख सके। शारिक अल्वी के लफ्जों से टपकती मदीने की तड़प ने ऐसा असर दिखाया कि बूढ़े हों या जवान, हर शख्स की पलकें भीग गईं और पूरा हॉल सिसकियों से गूंज उठा। शारिक अल्वी ने हज व उमरा के अरकान (धार्मिक क्रियाओं) को सिर्फ तकनीकी तौर पर नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर समझाते हुए बताया कि एहराम सिर्फ दो चादरें नहीं, बल्कि दुनियावी तकाल्लोफात से दूरी और खुदा के हुजूर फकीरी का लिबास है। उन्होंने जियारत के आदाब को इतने शालीन और सभ्य लहजे में बयां किया कि आज़मीन को ऐसा महसूस होने लगा मानो वे अभी से हुजूर (सल्ल.) के दयार में पहुंच गए हों। इस बा-बरकत मौके पर अफशीन हज ग्रुप इंडिया के सीएचजीओ मोईनुद्दीन कुरैशी, हिना ट्रैवल सर्विस के सगीर अहमद, रियाज़ टूर एंड ट्रैवल के सीईओ रियाज़ अहमद, चीफ ऑपरेशन (हज व उमरा) उमैर नजम शाह, शारिक बेग, मिनहाजुर्रहमान "टीपू", रेहान हाश्मी और शान इंटरप्राइजेज के सिराज अहमद व इसरार अहमद सहित शहर की कई मोअज्जिज शख्सियतें मौजूद रहीं। प्रोग्राम का सबसे जज्बाती लम्हा वह था जब शारिक अल्वी ने इख्तेताम (समापन) पर हाथ उठाए और आज़मीन के हक में दुआ की। उनकी रुआंसी आवाज और इल्तजा भरे अल्फाजों ने समां बांध दिया। इससे पहले रियाज़ टूर एंड ट्रैवल के चीफ ऑपरेशन उमैर नजम शाह ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी संस्था का मकसद सिर्फ सफर कराना नहीं, बल्कि हाजियों की ऐसी खिदमत करना है कि वे बिना किसी फिक्र के इबादत में मशगूल रह सकें। आज की यह महफिल महज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं रही, बल्कि आशिकों की एक ऐसी अंजुमन बन गई, जहाँ हर दिल में मदीना बसा था और हर आंख में काबा का दीदार था।

फीस वृद्धि के विरोध मे जानकीपुरम मे स्कूलों के खिलाफ धरना आयोजित लखनऊ

लोक तंत्र की शान, अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ

जानकीपुरम ब्राइट वे कॉलेज में फीस बढ़ाने को लेकर अभिभावकों ने किया स्कूल का घेराव, बच्चों की शिक्षा को व्यापार बनाना बन्द करों लूट की दुकान बन्द करो। के नारे लगाए। किताबों के आवश्यकता से काफी अधिक दाम, हर साल बढ़ती फीस, हर साल एडमिशन फीस, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। कितने बच्चों की पढ़ाई भी इसी सब वजहों से छूट रही है। हो भी क्यों न अधिकतर स्कूलों के मालिक नेता मंत्री और विधायक है। जो प्राइवेट स्कूल चला रहे है। जिसकी वजह से शासन प्रशासन भी अपना हाथ इस मामले से खींचे हुए है लेकिन देश में शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है इससे देश, और प्रदेश, पर राज करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जनता के सर से ऊपर पानी होता नज़र आ रहा है जिसकी शुरुआत लखनऊ के ब्राइट वे इण्टर कालेज जानकीपुरम् से की जा रही है।अभिभावकों का प्रदर्शन अब पुरे लखनऊ मे देखने को मिलेगा सूत्रों से जानकारी मिली है की आने वाले समय मे तमाम प्राइवेट स्कूलों के विरोध मे लखनऊ की जनता अब सड़को पर होंगी

सीता इंटर कॉलेज की मेधावी छात्रा बबिता यादव ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया

लोक तंत्र की शान

महमूदाबाद, सीतापुरः सीता इंटर कॉलेज की मेधावी छात्रा बबिता यादव ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा अयोध्या में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बबिता यादव पुत्री शिवराज यादव को शांतिकुंज के वरिष्ठ जनों द्वारा मेडल, प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार व क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। बबिता की इस सफलता पर सीता ग्रुप ऑफ एजूकेशन के चेयरमैन आरके वाजपेयी विरल, डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष, वागीश दिनकर वाजपेयी, उप प्रधानाचार्य यशपाल वर्मा, कार्यालय प्रमुख राकेश शुक्ल, व्यवस्था प्रमुख शिव सेवक मिश्र, सांस्कृतिक प्रमुख प्रतिभा सिंह समेत समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने बधाई दी।

पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शाहपुर गांव का मामला

लोक तंत्र की शान, अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ

सीतापुर जनपद के थाना बड्डूपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

मामले का संक्षिप्त विवरण-प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम शाहपुर निवासी मो. आमीन पुत्र मो. शफी की शिकायत पर पुलिस ने शादाब पुत्र रहमत अली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना की सूचना 1 अप्रैल 2024 को दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की विवेचना में जुटी थी।

पुलिस कार्यवाही और धाराए- विवेचना अधिकारी ने बताया कि केस डायरी (पर्चा नंबर 2) दिनांक 10 अप्रैल 2024 को ही प्रेषित की जा चुकी थी। आज यानी 12 अप्रैल को पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी शादाब को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 101/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की विभिन्न गंभीर धाराओं और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। दर्ज धाराओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैंः धारा 74, 332(C), 131, 352, 351(2), 64(1), 62 (BNSS) धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act)

गिरफ्तारी स्थल-गिरफ्तारी की यह कार्यवाही ग्राम शाहपुर, थाना बड्डूपुर क्षेत्र के अंतर्गत की गई है। पुलिस अब अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने की विधिक प्रक्रिया पूरी कर रही है। इस प्रकरण मे कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सोनकर ने बताया की उत्तर प्रदेश शाशन की मंशा के अनुरूप पुलिस के श्रीमान पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के आदेश के क्रम मे पुलिस उपाधिक्षक जगतराम कनौजिया के निर्देश पर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया पुलिस टीम मे योगेंद्र मिश्रा एस आई,सहित कई सिपाही शामिल रहे

संक्षिप्त समाचार

हाजीपुर में 17 वर्षीय आर्यन को गोली मारी, दो महीने पुरानी टक्कर का विवाद, घुटनों में लगी 2 बुलेट, आरोपी फरार

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के गर्दनिया चौक के पास सोमवार दोपहर एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के गर्दनिया चौक निवासी अनिल राय के 17 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। आर्यन कुमार ने पुलिस को बताया कि करीब दो महीने पहले सोनपुर जाते समय उसकी मोटरसाइकिल एक काली स्कॉर्पियो से टकरा गई थी। इस बात को लेकर गाली-गलौज हुई थी। आर्यन के अनुसार, उसे इंस्टाग्राम के जरिए पता चला कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी उसके दोस्त कृष कुमार का बड़ा भाई राहुल कुमार उस स्कॉर्पियो में था। सोमवार दोपहर जब आर्यन अपने घर से जढुआ जा रहा था, तभी उसके घर से थोड़ी दूर पर एक काली स्प्लेंडर बाइक पर सवार दो युवक मिले। इनमें औद्योगिक थाना क्षेत्र के पासवान चौक, चाणक्य कॉलोनी निवासी आदर्श कुमार और सुल्तानपुर निवासी राहुल कुमार शामिल थे। युवकों ने आर्यन को बाइक पर बैठने को कहा। जब आर्यन ने मना किया, तो उन्होंने उस पर दो गोलियां चलाईं। दोनों गोलियां आर्यन के दोनों पैरों के घुटनों में लगीं, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। हमलावर मौके से फरार हो गए।

खड़गपुर अग्निकांड, डीपी यादव ने पीड़ितों को दी आर्थिक मदद, सरकारी सहायता और पक्के आवास की मांग

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली के देसरी प्रखंड के खड़गपुर वार्ड संख्या 13 में हाल ही में भीषण अग्निकांड हुआ। इस घटना में 12 परिवारों के घर और उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और अब तक उन्हें प्रशासनिक स्तर से कोई ठोस मदद नहीं मिली है। सोमवार को भीखनपुरा गांव निवासी रेलवे यूनियन नेता और टीटी संघ के जोनल अध्यक्ष देवेंद्र यादव उर्फ डीपी यादव पीड़ितों से मिलने पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर घटना की विस्तृत जानकारी ली और प्रत्येक पीड़ित परिवार की समस्याओं को सुना। डीपी यादव ने तुरंत अपने स्तर पर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने घर बनाने के लिए करकट (टीन, लकड़ी, कील, छप्पर आदि) खरीदने हेतु नकद राशि दी। यह सहायता ऐसे समय में पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस दौरान डीपी यादव ने स्थानीय प्रशासन से कड़ी मांग की कि पीड़ित परिवारों को यथाशीघ्र सरकारी सहायता राशि जारी की जाए और उन्हें पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि आग से सब कुछ खत्म हो गया है और बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं रात में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। प्रशासन को तुरंत राहत सामग्री और आवास मुहैया कराने चाहिए। डीपी यादव ने समाज के अन्य लोगों से भी अपील की कि ऐसी विपदा की घड़ी में हर व्यक्ति को आगे आकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सामूहिक प्रयासों से ही पीड़ित परिवार जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। इस अवसर पर लोजपा नेता अजय पासवान सहित अन्य गणमान्य लोग और स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित थे। पीड़ितों ने डीपी यादव द्वारा की गई सहायता की सराहना की और सरकार तथा प्रशासन से भी ऐसी ही त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है। वर्तमान में पीड़ित परिवार तिरपाल और खंडहर में शरण लिए हुए हैं।

हाजीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, ईमेल के बाद पुलिस अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाई गई

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। आनन फानन में एसपी विक्रम सिहाग के निर्देश पर सदर एसडीपीओ दलबल के साथ कोर्ट पहुंचे और पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है वहीं मुजफ्फरपुर से बम निरोधक दस्ता को भी बुलाया जा रहा है। अफरा तफरी के बीच एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार ने बताया कि न्यायालय के ईमेल पर अज्ञात ईमेल से मेल आया है जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।वहीं एहतियात के तौर पर कोर्ट में इंट्री बंद कर दी गई है और किसी को भी कोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिला जज हर्षित सिंह के ईमेल पर कोर्ट उड़ने की धमकी मिली है। वहीं पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। कोर्ट के अंदर से अधिवक्ताओं के साथ साथ आम लोगों और दुकानदारों को भी कोर्ट परिसर से बाहर किया जा रहा है ताकि अच्छे से बम निरोधक दस्ता द्वारा जांच की जा सके। वहीं कोर्ट परिसर के साथ साथ आस पास के क्षेत्र की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आस पास स्थित सभी सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ लोगो की आवाजाही पर पुर्णतः रोक लगाया गया है। बहरहाल इस खबर के सामने आने के बाद से पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

वन विभाग की कार्रवाई पर काष्ठ शिल्पियों में नाराजगी, समिति ने अवैध जब्ती और पेड़ उखाड़ने का आरोप लगाया

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले में विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति की एक बैठक बभनी मठ राजापाकर में जयप्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में वन विभाग की कथित अवैध कार्रवाइयों के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया गया। समिति ने आरा मिलों की जब्ती और पेड़ों को मनमाने ढंग से उखाड़ने का आरोप लगाया। समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि वन विभाग द्वारा आरा मिलों को जब्त किया जा रहा है, लेकिन जब्ती सूची नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही, पेड़ों को भी मनमाने ढंग से उखाड़ा जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि वन विभाग कानून का पालन नहीं कर रहा है, जिससे काष्ठ शिल्पियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य वक्ता और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की एसएलसी समिति के सदस्य राम भरोस शर्मा ने विभागीय पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन गैर-कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ राज्यस्तरीय वन मंत्री के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए सभी को संगठित होना चाहिए। संगठन के प्रदेश महासचिव एवं मुख्य अतिथि शिव प्रसन्न ठाकुर ने जिला स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने जिला संगठन को मजबूत करने और एक जिला सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सम्मेलन से पहले प्रखंडों का दौरा किया जाएगा और वहां बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बैठक को मुकेश शर्मा, पंकज शर्मा, पूर्व मुखिया मोहन साह, जिला सचिव सुशील शर्मा, रामनाथ शर्मा, इंद्र शर्मा, मनोज शर्मा, गुड्डु शर्मा और संजय शर्मा सहित कई अन्य सदस्यों ने संबोधित किया। समिति ने 14 जून, 2026 को जिला सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पर विद्यार्थियों के विचार-विमर्श कार्यक्रम की रिपोर्ट

लोकतंत्र की शान

Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 2023 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करना है। इसी संदर्भ में, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, सहरसा द्वारा इस अधिनियम के त्वरित क्रियान्वयन तथा इसके व्यापक प्रभावों पर विचार-विमर्श हेतु एक छात्र चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 13 अप्रैल 2026 को इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, सहरसा के परिसर में आयोजित किया गया। इस चर्चा का विषय "राजनीति एवं नौकरशाही में महिलाओं की भूमिका" था, जिसमें शासन और लोक प्रशासन में महिलाओं की भूमिका, चुनौतियों एवं भविष्य की संभावनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. दीपक गोस्वामी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक (ARD) द्वारा किया गया तथा इसकी अध्यक्षता डॉ. एम. एन. ए. बैग, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक (SRD) ने की। कार्यक्रम में कुल 52 विद्यार्थियों (18 महिला एवं 38 पुरुष शिक्षार्थी) ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय केंद्र के 12 कर्मचारी, जिनमें SRD एवं ARD भी सम्मिलित थे, उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक क्षेत्रीय निदेशक द्वारा स्वागत भाषण के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानताओं को दूर करने में इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला तथा लोकतांत्रिक विमर्श में विद्यार्थियों की सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। इसके उपरांत, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक ने उद्घाटन वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए औपचारिक रूप से चर्चा सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने समावेशी शासन की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रतिभागियों को राजनीति एवं नौकरशाही में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं पर गंभीरता से विचार करने हेतु प्रेरित किया। इसके पश्चात कार्यक्रम खुली चर्चा सत्र में परिवर्तित हुआ, जिसमें पांच शिक्षार्थियों (तीन महिला एवं दो पुरुष प्रतिभागी) ने विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों ने लैंगिक पक्षपात, सामाजिक अपेक्षाएँ, संस्थागत अवरोध तथा नेतृत्व एवं निर्णय-निर्माण में महिलाओं की बदलती भूमिका जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए। यह चर्चा अत्यंत संवादात्मक एवं चिंतनशील रही, जिसने प्रतिभागियों को सार्थक संवाद एवं विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान किया।

चर्चा के दौरान हुई विचार-विमर्श एवं प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख संकल्प एवं सुझाव पारित किए गए:

1. सरकार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के प्रभावी अनुश्रवण एवं समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।

2. महिलाओं के सशक्तिकरण एवं नेतृत्व विकास के लिए शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

3. कुछ प्रतिभागियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि आरक्षण के अतिरिक्त महिलाओं को उनके योगदान का समुचित मान्यता, पुष्टि एवं समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि वे राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में सार्थक भूमिका निभा सकें।

कार्यक्रम का समापन सहायक क्षेत्रीय निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष, प्रतिभागियों एवं कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से महिला शिक्षार्थियों की सक्रिय एवं सारगर्भित सहभागिता की सराहना की। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक वातावरण में सभी प्रतिभागियों को अल्पाहार प्रदान करने के साथ हुआ। अंत में, सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने सभी शिक्षार्थियों को उनके उज्ज्वल शैक्षणिक एवं व्यावसायिक भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं।

'सबका सम्मान-जीवन आसान' कार्यक्रम में डीएम ने सुनीं समस्याएं, 30 आवेदनों के शीघ्र निपटारे के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा | मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः जिला प्रशासन सहरसा द्वारा सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत आयोजित ''सबका सम्मान-जीवन आसान'' (Ease of Living) कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में आम नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों के कुल 30 आवेदनों पर सुनवाई की गई। कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों—अंचलाधिकारी कहरा, नवहट्टा, सौर बाजार, सत्तर कटैया सहित अन्य को निर्देश दिया कि सभी मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जन-संवाद के दौरान कई आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। इनमें कहरा निवासी नृपेंद्र मिश्रा, नवहट्टा की प्रमिला देवी, सलखुआ के राहुल कुमार, सौर बाजार के सिकंदर साह, सत्तर कटैया के शत्रुघ्न पासवान तथा बनगांव के शशिधर ठाकुर शामिल थे। इन लोगों ने मुख्यतः राजस्व, भूमि विवाद और आपसी विवाद से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों—कहरा, सत्तर कटैया, सलखुआ, सौर बाजार एवं नवहट्टा—को इन मामलों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) श्री गणेश कुमार, अपर समाहर्ता श्री निशांत, जिला जनशिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी सह निदेशक एनईपी श्री पुलक कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जनगणना 2027: 17 अप्रैल से शुरू होगी स्व-गणना, सहरसा प्रशासन की नागरिकों से अपील

लोकतंत्र की शान

सहरसा |मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः जिला प्रशासन सहरसा ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे भारत की जनगणना 2027 के तहत निर्धारित अवधि 17 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 के बीच स्व-गणना (Self Enumeration) प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाएं। प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, जनगणना देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सरकार को जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, आवास तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से संबंधित सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं। ये आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं एवं जनकल्याणकारी नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्व-गणना प्रक्रिया पूरी तरह सरल, सुरक्षित और गोपनीय है। इसके लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज—जैसे आधार, पासपोर्ट या रेंट एग्रीमेंट—दिखाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी किसी अन्य विभाग के साथ साझा नहीं की जाएगी। प्रशासन ने यह भी बताया कि स्व-गणना केवल अधिकृत वेबसाइट se.census.gov.in के माध्यम से ही की जानी है तथा साइबर कैफे के माध्यम से यह प्रक्रिया अनुमन्य नहीं है। प्रवासी मजदूर एवं किराएदार व्यक्तियों को अपने वर्तमान

कार्यस्थल या निवास स्थान से ही गणना करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी सहरसा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जनगणना में दी गई सही और पूर्ण जानकारी ही जिले एवं राज्य के विकास की आधारशिला बनेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से समय पर स्व-गणना करने तथा अपने परिवार, पड़ोसियों और परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। किसी भी प्रकार की शंका या समस्या के समाधान हेतु संबंधित प्रखंड, नगर निकाय कार्यालय या जनगणना कर्मियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा 14 से 21 अप्रैल तक, सहरसा में 12 केंद्र निर्धारित

लोकतंत्र की शान

सहरसा | मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 14 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक (16 एवं 19 अप्रैल को छोड़कर) किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी—प्रथम पाली सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 12 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित परीक्षा केंद्रों में जिला स्कूल (कलेक्ट्रेट रोड), राजकीय कन्या उच्च विद्यालय (वीर कुंवर सिंह चौक), अनुग्रह नारायण सिंह स्मारक उच्च विद्यालय (जेल कॉलोनी), मनोहर उच्च विद्यालय (वीआईपी रोड, पूरब बाजार), एसएनएसआरकेएस कॉलेज (रिफ्यूजी कॉलोनी, बनगांव रोड), मनोहर उच्च विद्यालय (बैजनाथपुर), आरएम कॉलेज, रमेश झा महिला कॉलेज, एमएलटी कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक (गंगजला), एकलव्य सेंट्रल स्कूल (सुलिंदाबाद) तथा मंडन भारती कृषि

महाविद्यालय (अगवानपुर) शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा में लगभग 7980 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा के सुचारु संचालन एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सात जोनल दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, 29 स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी तथा दो उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, घड़ी (सामान्य या स्मार्ट) सहित किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी वस्तुएं भी प्रतिबंधित हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कदाचार मानते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कदाचार में संलिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा के साथ आगामी पांच वर्षों तक आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है, जबकि अफवाह फैलाने पर तीन वर्षों का प्रतिबंध लगाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की सघन जांच (फ्रिस्किंग) की जाएगी। प्रथम पाली के लिए सुबह 8:00 से 9:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली के लिए दोपहर 1:00 से 1:30 बजे तक जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि के उपरांत केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

बिहार कांग्रेस हर हफ्ते उठाएगा जनहित के मुद्दे

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार कांग्रेस अब राज्य से जुड़े गंभीर मुद्दों को जनता के सामने लेकर आएगी। इसे लेकर कांग्रेस "प्रेस से मिलिए" संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसे लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सभी जिलाध्यक्षों को लेटर भेजा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सप्ताह राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़े जनहित की गंभीर समस्याओं जैसे लूट, बलात्कार, घोटाले, शिक्षा, चिकित्सा, किसानी, मजदूरी से जुड़ी समस्याएं और अन्य अमानवीय घटनाएं को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

हर हफ्ते अपने जिले के गंभीर विषयों को बताना होगाः इसके तहत सभी जिलाध्यक्षों को हर हफ्ते अपने जिले के गंभीर विषयों का चयन कर प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय को अपडेट देना होगा। उन्हें जिलों से जुड़े जनहित की गंभीर समस्याओं के बारे में भेजना है।

प्रदेश कांग्रेस को भेजी गई प्रमाणिक सूचना के आधार पर प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित की जायेगी। इसमें अध्यक्ष के साथ पार्टी प्रवक्ता, संबंधित जिले के जिला कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश पर्यवेक्षक शामिल रहेंगे।

जनहित के मुद्दे उठाकर कांग्रेस संगठन मजबूत करने पर जोरः राजेश राम ने कहा कि, 'मुझे न केवल आशा है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जनहित के इन मुद्दों को गंभीरता से उठाकर हम प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय बनाएंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इसी तर्ज पर अपने-अपने जिलों में भी प्रत्येक सप्ताह "प्रेस से मिलिए" कार्यक्रम आयोजित करें और स्थानीय जन-मुद्दों को प्रखरता से उठाएं।

'लैंड फॉर जॉब' घोटाला मामले में लालू यादव की याचिका खारिज

लोकतंत्र की शान , पटना

लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़े ट्रायल को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। हालांकि, अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आंशिक राहत देते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल की कार्रवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के सामने व्यक्तिगत पेश होने की ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला लेने का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास रहेगा। यानी, अब निचली अदालत इस पूरे मामले की मेरिट पर सुनवाई करते हुए आगे की कार्रवाई

करेगी।

9 जनवरी 2026 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व CM लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजप्रताप, तेजस्वी यादव और बेटी मीसा, हेमा पर आरोप तय किए। लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय किया। इन लोगों पर अब मुकदमा चल रहा है।

कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया था। सुनवाई को लेकर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेजप्रताप-तेजस्वी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किया गया है।

छात्र राजद की रीब्रांडिंग, नया नाम और लोगो लांच

♦ **कैंपस राजनीति में पकड़ मजबूत करने की रणनीति, तेजस्वी अपनी नई टीम के साथ बढ़ेंगे आगे**

लोकतंत्र की शान , पटना

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की स्थापना (5 जुलाई 1997) के लगभग तीन दशक बाद पार्टी अपने छात्र संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सोमवार को छात्र राजद का नाम बदल दिया गया। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में नए नाम की घोषणा की। साथ ही नए Logo का भी अनावरण किया। तेजस्वी यादव ने कहा हमने छात्र राजद (CRJD), जो कि राजद का छात्र संगठन था, उसे भंग कर दिया है।

हमने अपनी पार्टी के नए छात्र संगठन का नाम 'सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' रखा है। बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसके पास बिहार की जनता का जनादेश नहीं होगा। अब बिहार की सरकार गुजरात से संचालित होगी।

जेडीयू अब बीजेपी का एक संगठन बन चुकी है। आप देखेंगे कि दो महीने बाद कोई भी नीतीश कुमार की परवाह नहीं करेगा।

छात्र राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है राजदः यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी छात्र राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। इससे पहले लालू यादव ने 6 मार्च को छात्र राजद की बिहार इकाई को भंग कर दिया था। इसके बाद से छात्र राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नवल किशोर यादव नए नाम और लोगो को अंतिम रूप देने में जुटे थे। रविवार को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी।

कैंपस में दबदबा बढ़ाने की तैयारीः राजद की रणनीति साफ है कि वह भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह विश्वविद्यालय परिसरों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी, सीपीआई के एआईएसएफ, सीपीएम के एसएफआई और माले के आईसा की तरह राजद भी अपने छात्र संगठन को सक्रिय और प्रभावी बनाना चाहता है। इसके जरिए पार्टी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य हिंदी भाषी राज्यों में अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है।

MY समीकरण से आगे बढ़ने की कोशिशः राजद अब अपने पारंपरिक MY (मुस्लिम-यादव) वोट बैंक से आगे बढ़कर अन्य वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश में है। पार्टी का मानना है कि छात्र संगठन के जरिए नए सामाजिक समूहों को जोड़ा जा सकता है और भविष्य के नए नेतृत्व को तैयार किया जा सकता है।

तेजस्वी की नई टीम, तेजप्रताप का असर खत्मः वर्ष 2011 से 2025 तक छात्र राजद की कमान अनौपचारिक रूप से लालू प्रसाद के बड़े बेटे Tej Pratap Yadav के हाथों में रही। इस दौरान छात्र संगठन में उनका वर्चस्व बना रहा और कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। इसी मुद्दे को लेकर उनकी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से तनातनी भी हुई थी।

संक्षिप्त समाचार

एडवोकेट अमित शुक्ला एवं श्रीमती मनोरमा शुक्ला की सुपुत्री खुशी शुक्ला ने अटल बिहारी बाजपेई मेडिकल कॉलेज, विदिशा से MBBS की डिग्री प्राप्त कर परिवार व क्षेत्र का मान बढ़ाया है

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेशः एडवोकेट अमित शुक्ला एवं श्रीमती मनोरमा शुक्ला की सुपुत्री खुशी शुक्ला ने अटल बिहारी बाजपेई मेडिकल कॉलेज, विदिशा से MBBS की डिग्री प्राप्त कर परिवार व क्षेत्र का मान बढ़ाया है। कुलपति महोदय ने उन्हें डिग्री प्रदान करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। खुशी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के साथ-साथ अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा को दिया।

यमुनानगरःजनगणना तैयारियों के बीच शिक्षकों की ड्यूटी से पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका

लोकतंत्र की शान : यमुनानगर। जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच यमुनानगर में शिक्षण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षकों को गणनाकर्मी के रूप में नियुक्त किए जाने से स्कूलों में पढ़ाई पर असर को लेकर चिंता सामने आई है। जिले में करीब 3600 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 2838 शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया गया है। पहले से ही शिक्षकों की संख्या सीमित है, वहीं कुछ शिक्षक हाल ही में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ आगामी महीनों में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में स्कूलों में स्टाफ की कमी और बढ़ सकती है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष रोस्टर तैयार किया गया है। इसके तहत शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से जनगणना कार्य में लगाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। उपायुक्त प्रीति ने लघु सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जनगणना 2027 को दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहला चरण 'मकान सूचीकरण एवं भवन गणना' एक मई से 30 मई 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक आयोजित होगा, जिसमें जनसंख्या का विवरण एकत्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा भी दी जा रही है। यह प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जिसमें लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर आधारित सत्यापन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के अनुसार, पोर्टल पर घर की लोकेशन दर्ज करने के बाद निर्धारित प्रश्नों के उत्तर भरने होंगे। जानकारी जमा करने के बाद एक विशिष्ट आईडी प्राप्त होगी, जिसे सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

पानीपतः मारपीट में घायल युवक की पीजीआई में मौत, अब हत्या का केस दर्ज

लोकतंत्र की शान : पानीपत। पानीपत के गांव राणा माजरा में मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट मामले में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नौ अप्रैल को दो युवकों द्वारा बेरहमी से पीटे गए 23 वर्षीय रिंकू की रविवार देर रात रोहतक पीजीआई में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने पहले से दर्ज मारपीट के मामले में अब हत्या की धारा जोड़ कर नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के पिता श्रीपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नौ अप्रैल की शाम उनका पूरा परिवार खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था। शाम के समय गांव का ही प्रवीन उनके पास आया और रिंकू को बराना गांव चलने के बहाने अपने साथ ले गया। रास्ते में उन्हें सोनू मिला और तीनों साथ चल दिए। शिकायत के अनुसार, रास्ते में आश्रम के पास पहुंचते ही प्रवीन और सोनू ने अचानक रिंकू पर हमला कर दिया। दोनों ने रिंकू को नीचे गिराकर लात-घूंसों व डंडों से बुरी तरह पीटा।हैवानियत की हदें पार करते हुए हमलावरों ने मोटरसाइकिल की चाबी रिंकू के सिर के पिछले हिस्से में घोंप दी। चोट इतनी गहरी थी कि रिंकू के कान से खून का बहाव रुक ही नहीं रहा था। गंभीर हालत में घायल रिंकू को पहले गढ़ी बेसिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पानीपत सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। पानीपत के डॉक्टरों ने रिंकू की नाजुक हालत देखते हुए उसे तुरंत रोहतक पीजीआई भेज दिया। तीन दिनों तक वेंटिलेटर और डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद आखिरकार 12 अप्रैल की रात रिंकू ने आखिरी सांस ली। इस मामले में सनौली खुर्द थाना पुलिस ने पहले मारपीट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अब रिंकू की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा जोड़ दी है।

गर्मी के चलते बदला अदालतों का समयः सुबह 8 बजे से शुरू होगी सुनवाई

लोकतंत्र की शान : जयपुर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट सहित सभी न्यायालयों में सोमवार से ग्रीष्मकालीन समय सारिणी लागू कर दी गई है। यह नया समय 28 जून तक प्रभावी रहेगा। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब जोधपुर मुख्यपीठ, जयपुर खंडपीठ और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य सुबह जल्दी शुरू होगा। हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य अब सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक होगा। इस दौरान न्यायाधीशों के लिए सुबह 10:30 से 11 बजे तक आधे घंटे का मध्याह्नकाश निर्धारित किया गया है। वहीं, रजिस्ट्री और अन्य कार्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर एक बजे तक संचालित होंगे, जिसमें कर्मचारियों के लिए 10:30 से 10:45 बजे तक 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। जिला एवं सेशन न्यायालयों सहित सभी अधीनस्थ अदालतों में भी समय परिवर्तन लागू किया गया है। यहां अब सुनवाई सुबह आठ बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इन अदालतों में सुबह 10 से 10:15 बजे तक 15 मिनट का मध्यावकाश रखा गया है। वहीं, कार्यालय समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा। पीठासीन अधिकारियों को चेंबर वर्क के लिए भी अलग समय निर्धारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश सुबह 7:30 से 8 बजे तक और दोपहर 12:30 से एक बजे तक चेंबर में बैठकर आदेश लेखन एवं प्रशासनिक कार्य करेंगे। गौरतलब है कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में न्यायालयों के समय में बदलाव किया जाता है, ताकि न्यायिक कार्य प्रभावित हुए बिना कर्मचारियों और वादकारियों को राहत मिल सके।

मलमास समाप्ति के साथ लौटेगी रौनकः 19 अप्रैल से शुरू होंगे विवाह मुहूर्त

लोकतंत्र की शान : जयपुर। प्रदेश में पिछले एक महीने से मांगलिक कार्यों पर लगा विराम अब समाप्त होने जा रहा है। 14 अप्रैल (मंगलवार) को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ ही मलमास (खरमास) खत्म हो जाएगा और शुभ कार्यों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त होगा। ज्योतिषाचार्य रिषांक शर्मा के अनुसार सूर्य के मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते ही मलमास समाप्त हो जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब सूर्य बृहस्पति की राशि मीन में रहता है, तब मलमास माना जाता है और इस दौरान विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल से गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, सगाई (टीका), नए व्यापार की शुरुआत और वाहन व संपत्ति खरीद जैसे शुभ कार्य पुनः शुरू हो सकेंगे। हालांकि विवाह जैसे बड़े मांगलिक आयोजनों के लिए लोगों को कुछ दिन और इंतजार करना होगा। पंचांग के अनुसार विवाह के शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल से प्रारंभ होंगे। इस दिन अक्षय तृतीया (आखा तीज) का अबूझ सावा होने के कारण बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे।

माथा टेका, भगवान के चरण स्पर्श कर चुरा ले गया मुकुट

» आस्था के नाम पर हैरान कर देने वाली चोरी, सीसीटीव्ही में कैद हुई वारदात

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। शहर के कन्या महाविद्यालय के सामने स्थित भगवान हनुमान और भगवान शनि देव के मंदिर में चार दिन में दो मर्तबा हुई चोरी की वारदात ने लोगों को हैरान कर दिया है। यह घटना सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि आस्था के साथ एक अजीब विरोधाभास भी पेश करती है, क्योंकि चोर ने वारदात को अंजाम देने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की। मिली जानकारी के मुताबिक प्रथम चोरी में 9 अप्रैल की रात करीब 1 बजे एक अज्ञात व्यक्ति मंदिर में दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वह पहले मंदिर के बाहर अपने जूते उतारता है, फिर गेट को छूकर प्रणाम करता है। इसके बाद वह अंदर प्रवेश करता है और भगवान हनुमान की मूर्ति के पास पहुंचकर श्रद्धा से सिर झुकाता है। वहीं इसके बाद वह हनुमान जी के मुकुट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब सफल नहीं होता तो उनके गालों को छूकर मानो आशीर्वाद लेता है और उन्हें चूमता है। फिर वह पीछे स्थित भगवान शनि देव के मंदिर की ओर जाता है, वहां भी प्रणाम करता है और मौके का फायदा उठाकर शनि देव का चांदी का मुकुट चोरी कर अपने पास रख लेता है। इन सबमे हैरानी की बात यह है कि दूसरी मर्तबा 12 अप्रैल की रात लगभग उसी समय वह चोर फिर से मंदिर पहुंचता है। इस बार वह सीधे हनुमान जी के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनका चांदी का मुकुट व हाथों के कड़े चुरा लेता है। वारदात के बाद वह फिर से भगवान के चरण स्पर्श करता है, बाहर जाकर अपने जूते पहनता है और आराम से निकल जाता है। आज सोमवार सुबह जब पुजारी अमित मिश्रा मंदिर पहुंचे तो दोनों घटनाओं का खुलासा हुआ। पहले शनि देव और फिर हनुमान जी के आभूषण चोरी होने से मंदिर में हडकंप मच गया। पुजारी ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखा और पुलिस को सूचना दी। चोरी गए हनुमान जी के मूर्ति में लगे चांदी के मुकुट की कीमत 20 हजार रुपए तथा शनि जी महराज की मूर्ति से चोरी गए चांदी के मुकुट की कीमत 10 हजार आंकी गई है। चांदी के दोनो मुकुट की कीमत 30 हजार रुपए आंकी गई। कोतवाली थाना में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 331(4), 305(डी) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय निवासी बृजभूषण मिश्रा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एक ही मंदिर में चार दिन के भीतर दो बार चोरी होना काफी गंभीर मामला है।

अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान तेज 31 प्रकरण दर्ज, 108 लीटर शराब जब्त

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी संतोष सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। 01 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के बीच अवैध मदिरा विक्रय केंद्रों एवं ढाबों पर कार्रवाई करते हुए कुल 31 प्रकरण दर्ज किए गए तथा 108 लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई। सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(ए) एवं (एफ) के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं। अभियान के दौरान यह भी पाया गया कि मदिरा दुकानों के आसपास नमकीन, चना एवं अंडे के ठेलों पर लोगों का जमावड़ा रहता है। इस पर कार्रवाई करते हुए 12 अप्रैल 2026 को शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक विशेष अभियान चलाकर ऐसे ठेले हटवाए गए। साथ ही अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित किया गया कि मदिरा दुकानों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए ठेले लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रखने की बात कही गई है।

अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा जिले के सभी विकास खंडो में दिया ज्ञापन

लोकतंत्र की शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

मुरैना - अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर के साथ मुरैना जिले के सभी विकास खंडो में टीचर एजिबिलिटी टेस्ट(TET) परीक्षा के विरोध में ज्ञापन दिए गए अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक रामनरेश दंडोतिया, जनक सिंह रावत ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर जिले के अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, कैलारस, पहाड़ गढ़, सबलगढ़ में रैली निकाल कर तथा नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, पुरानी पेंशन टेट परीक्षा रद्द करने संयुक्त मोर्चा के ब्लॉक संयोजकों के नेतृत्व में प्रत्येक विकासखंड में ज्ञापन दिया गया मुरैना में रामनरेश दंडोतिया मुन्नालाल शर्मा पवन परिहार जौरा में जीतेन्द्र सिंह यादव,उमेश शर्मा, रवि शंकर शर्मा, जनक सिंह रावत नरेंद्र सिंह तोमर सबलगढ़ में हरेंद्र सिंह परमार, पटवारी सिंह गुर्जर, योगेंद्र शर्मा, मोहन लाल तिवारी पोरसा में भंवर सिंह तोमर अम्बाह में शैलेन्द्र सिंह तोमर पहाड़ गढ़ में के के शर्मा कैलारस में केशव शुक्ला एवं संयुक्त मोर्चा के ब्लॉक संयोजकों के नेतृत्व रैली निकालकर सरकार से मांग की गई टेट परीक्षा को रद्द करें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता ने एवं पुरानी पेंशन बहाल करें 18 अप्रैल को जंबूरी मैदानभोपाल मे विशाल आंदोलन होगा सभी कर्मचारियों से भोपाल में अधिक से अधिक संख्या में जाने की अपील की

रेत माफिया की क्रूरता के विरोध में सीधी में कैंडल मार्च, शहीद वनरक्षक हरकेश गुर्जर को दी श्रद्धांजलि

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)लोकतंत्र की शान

सीधी। 04 अप्रैल 2026 को वन मंडल मुरैना क्षेत्र में रेत माफिया द्वारा वनरक्षक श्री हरकेश गुर्जर की ट्रैक्टर से कुचलकर की गई निर्मम हत्या के विरोध में सीधी जिले के वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। यह कैंडल मार्च कार्यालय क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व से प्रारंभ होकर सामान्य वन मंडल सीधी तक निकाला गया। इस दौरान सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शहीद वनरक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वन मंडल अधिकारी सीधी, उप वन मंडल अधिकारी सीधी एवं मझौली, सहायक संचालक संजय टाइगर रिजर्व, रेंजर, डिप्टी रेंजर एवं वनरक्षक सहित समस्त वन अमला उपस्थित रहा। सभी ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर वन अधिकारियों ने शासन-प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि वन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो प्राकृतिक संपदा की रक्षा करते हुए इस प्रकार की घटनाएं लगातार चुनौती बनी रहेंगी। साथ ही वन कर्मचारी संघ सीधी द्वारा शहीद वनरक्षक के परिजनों की सहायता हेतु आर्थिक सहयोग भी एकत्र किया जा रहा है। उप वन मंडल अधिकारी सीधी ने अपने संबोधन में कहा कि वनरक्षक श्री हरकेश गुर्जर का अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा सदैव याद रखी जाएगी। उन्होंने सभी वन कर्मचारियों से अपील की कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। श्रद्धांजलि सभा में परिक्षेत्र अधिकारी मोहन, बस्तुआ, सोनघड़ियाल सहित जिले के सभी वनकर्मी उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में शहीद वनरक्षक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

गरीबों का आशियाना उजाड़ने साजिश,गौ शाला के बहाने जमीन हथियाने का आरोप

» विधायक व कलेक्टर से ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार

लोकतंत्र की शान, ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख

सीधी। एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा बैगा जनजाति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए "जन मन" योजना संचालित की गई है जिसके तहत प्रत्येक बैगा परिवार को आवास के साथ-साथ बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऐसी योजना लागू की गई है वहीं दूसरी तरफ जिले की जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरौला में गौशाला निर्माण के लिए चिन्हित की गई भूमि जिसमें तीन दशक पूर्व से दर्जन पर बैगा परिवार एवं अन्य आदिवासी परिवार कुल आधा सैकड़ा लोग आबाद हैं उन्हें उजाड़ने की साजिश चल रही है। चिन्हित आराजी में तीन दशक पूर्व से आवाद ग्रामीण क्षेत्रीय विधायक व कलेक्टर से जनसुनवाई में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदक केशव प्रसाद पिता महावीर साहू एवं रामलाल यादव पिता छोटे लाल यादव द्वारा कलेक्टर जनसुनवाई में 7 अप्रैल 2026 को दिए गए आवेदन में 22 बैगा जनजाति के एवं 6 अगरिया आदिवासी के अलावा लगभग आधा सैकड़ा लोगों के द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि ग्राम सिरौला की आराजी नंबर 712 एवं 713 में तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच,सचिव एवं हल्का पटवारी के द्वारा गौशाला निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है जबकि उक्त आराजी के चारों तरफ बसाहट है एवं स्कूल और आंगनबाड़ी भी संचालित है।और शिकायतकर्ता दो से तीन दशक पूर्व से आवाद हैं जो पूरी तरह भूमिहीन हैं।अगर चिन्हित आराजी में गौशाला निर्माण होता है तो वह बेघर हो जाएंगे जबकि ग्राम सिरौला की आराजी नंबर 1802 मध्य प्रदेश शासन दर्ज है वह रोड एवं जंगल से लगी है एवं बारहमासी नाला बहता है एवं वह जमीन बंजर भी है जिसमें कोई कब्जाधारी भी नहीं है।आवेदन में मांग की गई है कि चिन्हित आराजी एवं अन्य आरजी जिसमें सुझाव दिया गया है दोनों की जांच की जाए एवं उपयुक्त स्थान में ही गौशाला का निर्माण किया जाए।

इनका कहना है। हम ग्रामीणों द्वारा आधा सैकड़ा की संख्य में हस्ताक्षर कर कलेक्टर की जनसुनवाई एवं क्षेत्रीय विधायक के पास आवेदन देकर न्याय की मांग किए हैं कि हम भूमिहीनों के आशियाने को ना उजाड़ा जाए।जिसमें विधायक द्वारा भी आश्वासन दिया गया है।

केशव प्रसाद साहू, फरियादी ग्रामीण। जब गांव में पर्याप्त मात्रा में जंगल के किनारे जमीन उपलब्ध है तो बस्ती के बीच में गौशाला प्रस्तावित करना साजिश है। हम गरीब बैगा परिवारों को उजाड़ने की नीयत से इस जमीन को प्रस्तावित किया गया है शासन से न्याय की मांग करते हैं।

सीताराम बैगा, ग्रामीण। जब ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है कि बस्ती के बाहर जंगल के किनारे आराजी नंबर 1802 में गौशाला बनवाया जाए।पूर्व प्रस्तावित आराजी में उपयुक्त नहीं है।उसका पालन होना चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए।

नानदानी बैगा, ग्रामीण। अगर पूर्व में गौशाला के लिए प्रस्ताव और जिओ टैग किया गया है तो उस पर ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त जमीन में गौशाला बनवाया जाए चिन्हित जमीन उपयुक्त नहीं है और मैंने भी क्षेत्रीय विधायक से मांग की है कि दोनों जमीन की जांच कर जहां उपयुक्त हो वहां स्वीकृति दें ताकि गौशाला का निर्माण हो सके।

रैना द्विवेदी, सरपंच सिरौला।

पलवल में 18 साल से फरार गोकशी का आरोपी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

पलवल। बहीन थाना पुलिस ने गोकशी के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 18 साल से फरार चल रहे भगोड़ा आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत द्वारा पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान कोट गांव निवासी इस्लाम के रूप में हुई है। वह बहीन थाना सहित अन्य थानों में दर्ज कई मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू किया। इस मामले में पहले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी के खिलाफ बहीन थाना में वर्ष 2008, 2020, 2021 और 2023 के अलावा हथीन थाना में वर्ष 2000 और सोहना थाना में वर्ष 2010 में विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि उससे अन्य मामलों के संबंध में भी जानकारी हासिल की जा सके। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि भगोड़ा घोषित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

यमुनानगर में स्मैक तस्करी के मुख्य सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया

लोकतंत्र की शान

यमुनानगर। यमुनानगर पुलिस की अपराध शाखा-1 ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए सोमवार को मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपराध शाखा-1 के प्रभारी राजकुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पांजूपुर नहर पुल के पास से शादीपुर निवासी इल्ताफ को 16 ग्राम हेरोइन (स्मैक) के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह यह नशीला पदार्थ सहारनपुर जिले के गांव दुम्झेडा निवासी मुनशेद से खरीदकर लाया था। पुलिस ने आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सप्लाई चेन तक पहुंच बनाई और मुख्य सप्लायर मुनशेद को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रभारी राजकुमार ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

सुशील कोल ने अशोक साहू पर बीड़ी के लिए के पैसे ना देने पर बाके से किया घातक हमला अस्पताल से किया रेफर जबलपुर अपराधी खुलेआम घूम रहा

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनीः बिगत दिनों जानकारी अनुसार अशोक साहू केद्वारा प्रातः 5:00 बजे महुआ बिनने जंगल जाते समय गांव के तलैया पहुंचे उसी समय सुशील कोल के द्वारा मेरी तरफ आते हुए पहुंच और मुझे बिडी मांगने लगा मेरे पास नहीं थी और मैं मना कर दिया तब उसने मुझे गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगा और मां बहन की गाली और गंदी-गंदी गाली दे रहा था हाथ मे लोहे दार घातक हथियार बांका लिए हुए था जिस पर मुझ पर हमले करने लगा और कहने लगा मुझे पैसे दो बीड़ी खरीदने के लिए ,नहीं देने पर मेरे ऊपर हमला कर दिया ।और मेरे बाएं तरफ माथे में और बाएं हाथ की गंधेली चोट मारा जिस पर खून निकलने लगा मैं चिल्लाया पीछे मेरा भाई गणेश साहू काशी राम साहू मुझे बचाने दोड़े सुशील कोल के द्वारा मुझे धमकी देने लगा और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मेरा पुत्र काशीराम सहू तुरंत शासकीय अस्पताल बचाने के लिए दौड़े और अस्पताल के वार्ड नंबर 1 मे ऑर्थोपेडिक वार्ड वार्ड भर्ती किया और इलाज रात मे इलाज होने लगा मेरे माथे में टांके लगे और बगल में भी चोटे आई सुशील कोल के खिलाफ आने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर तात्पर्य दिखाते हुए पुलिस ने कार्यवाही की थाना एन के जी कटनी के द्वारा मामला कायम कर अपराध क्रमांक 0/26 भारतीय दंडसहिता धारा 296/बी 118(1)119(1)351(3)के तहत एफ आई आर दर्ज की और और कार्रवाई शुरू कर दी यह भी जानकारी मिली है कि अपराधी को गांव के सरपंच ललिता विनोद तिवारी सरपंच पति के द्वारा सुशील कोल को एनकेजीथना मेंगिरफ्तार गिरफ्तार कराया। अभी जानकारी मिली एनके जी। थाने प्रभारी के द्वारा उसे बाद में छोड़ दिया जिस गांव में एक एक दहशत का माहौल है पुलिस के के द्वारा क्या कारण है कि अपराधी को क्योंछोड़ दिया गया इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी मगर खुलेआम अपराधी घूम रहा है कोई दूसरीघटना ना घट उसे गिरफ्तार बंद किया जए अशोक साहू डॉक्टर के द्वारा रिपोर्टके अंदरूनी चोटहोने के के कारण उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया जिला प्रशासन को चाहिए ऐसे अपराधीको गिरफ्तार कर कार्रवाई करें ताकि उसे न्यायमिल सके।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल में सरकारी विज्ञापन नीति का विरोध, अखबारों ने पहले पृष्ठ पर नहीं छापे समाचार

काठमांडू। नेपाल से प्रकाशित कुछ प्रमुख अखबारों ने सोमवार को पहले पृष्ठ पर समाचार नहीं प्रकाशित किये। इसके बजाय प्रश्नवाचक चिन्ह प्रकाशित करके सरकारी विज्ञापन नीति का विरोध जताया है। काठमांडू से प्रकाशित दैनिक नेपाल समाचारपत्र, कारोबार, राजधानी, आर्थिक अभियान, सौर्य, मध्यान्ह, प्रभाव, प्रक्षेपण आदि ने यह कदम उठाया है। इसी तरह काठमांडू से बाहर प्रकाशित ब्लास्ट टाइम्स, बुटवल टुडे, दैनिक पत्र, लुम्बिनी, सुदूर सन्देश, मिशन टुडे, कंक्रिविहार सहित अन्य अखबारों ने भी पहले पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित नहीं किए हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने 1 अप्रैल को निजी मीडिया में सरकारी सूचना प्रकाशित न करने का प्रावधान किया है। फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन प्रकाशकों ने सार्वजनिक निकायों के सार्वजनिक खरीद समेत सभी सरकारी सूचनाएं केवल सरकारी मीडिया में ही प्रकाशित और प्रसारित करने के निर्णय के विरोध में पहले पृष्ठ पर समाचार की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रकाशित किए हैं। काठमांडू से प्रकाशित होने वाले मध्याह्न दैनिक के प्रधान संपादक मदन कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि मीडिया एलायंस और मीडिया सोसाइटी से परामर्श के बाद यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के उस निर्णय पर सवाल उठाया है, जो संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को छीनता है। नेपाल पत्रकार महासंघ की अध्यक्ष निर्मला शर्मा ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि सरकार का यह निर्णय संविधान के सुनिश्चित प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। उनके अनुसार इससे श्रमजीवी पत्रकारों और उनके स्व-रोजगार के अधिकारों का भी हनन हुआ है।

पतंजलि ट्रस्ट के जमीन धांधली मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा नेपाल सुप्रीम कोर्ट

काठमांडू। नेपाल में पतंजलि ट्रस्ट के जमीन धांधली मामले में उच्चतम न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सह-संयोजक माधव कुमार नेपाल पर इससे संबंधित भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के बाद पतंजलि योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालय के नाम पर दी गई जमीन में अनियमितता के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल पर 18 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति मांग के साथ ५ जून, २०२५ को भ्रष्टाचार का मामला विशेष अदालत में दायर किया गया था। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री के निर्देश पर संबंधित मंत्रालय ने उक्त कंपनी द्वारा गैरकानूनी रूप से प्राप्त सीमा से अधिक जमीन को भूमि संबंधी कानून के अनुसार जब्त कर सरकारी संपत्ति घोषित करने के बजाय, उसे बेचने और अदला-बदली की अनुमति देने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में सीधे तौर पर पेश किया गया था।

ब्यूरो के बयान के अनुसार इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद बैठक में पतंजलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कंपनी को पहले खरीदी गई चलाल गणेशस्थान, सांगा और महेन्द्रज्योति गांव में सीमा से अधिक जमीन बेचने और अदला-बदली करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया। उसी निर्णय के अनुसार तत्कालीन मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरे ने उसके कार्यान्वयन के लिए पत्राचार किया। साथ ही यह भी पाया गया कि मंत्रिपरिषद और उसकी विधेयक समिति के निर्णय से पहले ही सनराइज बैंक लिमिटेड से उक्त अतिरिक्त जमीन को गिरवी रखकर ऋण लिया जा चुका था। हालांकि, एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से पहले दाखिल की गई चार्जशीट में कैबिनेट के नीतिगत फैसले का हवाला देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल पर मुकदमा नहीं चलाने की बात कही गई थी। बाद में नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में फैसला दिया कि जब मामला नीतिगत भ्रष्टाचार का हो, तो कैबिनेट के फैसले के खिलाफ जांच हो सकती है और प्रधानमंत्री को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

तेलंगाना के सरकारी स्कूल में एआई से पढ़ाई, 105 सीटों के लिए 3500 आवेदन आए

हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 104 किमी दूर नलगोंडा स्थित कोमटिरेड्डी प्रतीक सरकारी स्कूल का पूरी तरह कायाकल्प किया गया है। अब यह एसी कैंपस, 36 स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी और एआई आधारित पढ़ाई से लैस मॉडल सरकारी स्कूल बन गया है। स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर है। कक्षा 2 और 3 के लिए खेल व गतिविधि आधारित शिक्षण, कहानी, फॉनिक्स, ऑडियो-वीडियो और प्रैक्टिकल लर्निंग की व्यवस्था की गई है।

पर्यावरण शिक्षा के लिए किचन गार्डन भी बनाया गया है। स्कूल में स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, डाइनिंग हॉल और हर मंजिल के लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। ये सभी सुविधाएं छात्रों को पूरी तरह निःशुल्क दी जा रही हैं। तेलंगाना के सड़क और भवन मंत्री कोमटिरेड्डी ने अपने ट्रस्ट से 8 करोड़ रुपये खर्च कर स्कूल का पुनर्निर्माण कराया है। सीटें सीमित होने से समय पर आवेदन करने वाले छात्रों को ही प्रवेश मिला है। इससे एडमिशन के लिए पैरेंट्स की लंबी लाइन लग रही हैं। स्कूल में 12 शिक्षक और करीब 250 बच्चे हैं। अब तक 3500 आवेदन फार्म अभिभावक ले जा चुके हैं। इनमें से 2084 आवेदन फार्म जमा भी हो गए हैं। लेकिन सीटें सिर्फ 105 हैं। मंत्री ने सरकार को प्रपोजल दिया है कि इस स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि मेरे 19 साल के बेटे प्रतीक की 2011 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसकी याद को बनाए रखने के लिए मैंने मन बनाया था कि बेटे की याद में एक स्कूल बनाऊंगा या किसी स्कूल की मदद करूंगा, जहां शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।

चेस्टर हिल मामला, सीएस के बाद सीएम पर निशाना, पूर्व सीएस बोले- हरियाणा ने कार्रवाई की

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का कथित चेस्टर हिल भूमि खरीद घोटाला तूल पकड़ रहा है। रेरा के पूर्व चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी के बाद अब पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने भी हिमाचल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। BJP के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जमवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अफसरों पर कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें शेल्टर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सचिवालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले अफसरों पर सीएम को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेस्टर हिल मामला सीबीआई को देने की मांग की। जमवाल ने कहा कि अधिकारियों के बीच खुले आरोप-प्रत्यारोप सरकार के भीतर समन्वय की कमी और कमजोर नेतृत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा- प्रदेश में ऐसी स्थिति पहली बार बनी है जब अधिकारी सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इससे पहले, श्रीकांत बाल्दी ने चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोला। बाल्दी ने संजय गुप्ता के दो आदेशों को 'अवैध' करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि वह जल्द शिमला आकर इस मसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेंगे। श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि संजय गुप्ता ने पहले SDM सोलन की चेस्टर हिल प्रोजेक्ट की भूमि खरीद में गड़बड़ी उजागर करने वाली जांच रिपोर्ट को दबाया। इस रिपोर्ट में भूमि कानून (सेक्शन 118) के उल्लंघन की बात सामने आई थी। इसके बाद, संजय गुप्ता ने नगर निगम सोलन द्वारा अवैध निर्माण को गिराने के कमिश्नर के आदेश को भी रद्द कर दिया। बाल्दी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के दोनों आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। बाल्दी ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया।

पाकिस्तान को 46,500 करोड़ की मदद देंगे सऊदी-कतर

इससे यूएई का 29,000 करोड़ कर्ज चुकाएगा, पैसे लौटाने के लिए सिर्फ 11 दिन बाकी

एजेंसी, नई दिल्ली

पाकिस्तान को सऊदी अरब और कतर से 5 अरब डॉलर (लगभग 46,500 करोड़ रुपए) की वित्तीय मदद मिलेगी। यह मदद ऐसे समय में आ रही है, जब देश को इस महीने के अंत तक UAE को 3.5 अरब डॉलर (लगभग 29,000 करोड़ रुपए) चुकाने हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की कमजोर विदेशी मुद्रा स्थिति संभालने के लिए यह मदद अहम मानी जा रही है। UAE ने हाल ही में कर्ज रोलओवर की नीति में बदलाव किए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने अप्रैल तक UAE का 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने का फैसला किया।

तय शेड्यूल के मुताबिक 23 अप्रैल तक पाकिस्तान को इस कर्ज की आखरी किस्त देनी है। इसका मतलब कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 11 दिन का समय बाकी है। इसके अलावा, अप्रैल में पाकिस्तान को कुल करीब 4.8 अरब डॉलर

चुकाने हैं, जिसमें एक बड़ा बॉन्ड भी शामिल है।

IMF की पाकिस्तान में पैसे बनाए रखने की शर्तः IMF ने पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए 3 साल का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत उसे करीब 7 अरब डॉलर की मदद मिलेगी। इसके बदले IMF ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान के बड़े कर्जदाता सऊदी अरब, चीन और UAE अपने कर्ज के पैसे 3 साल तक तक पाकिस्तान में ही रखेंगे, यानी वे पैसा वापस नहीं निकालेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगे चलकर कतर, UAE की जगह ले सकता है।

अप्रैल अंत तक UAE का पैसा चुकाना हैः UAE ने हाल में कर्ज रोलओवर की नीति बदलकर शॉर्ट-टर्म एक्सटेंशन शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान पर जल्दी भुगतान का दबाव बढ़ा। इसके बाद पाकिस्तान ने UAE का 3.5 अरब डॉलर यानी करीब 29,000 करोड़ रुपए का कर्ज 11, 17 और 23 अप्रैल को अलग-अलग किस्तों में लौटाने का फैसला लिया। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा पहले ही दूसरे देशों की मदद पर टिका है। ये कर्ज पाकिस्तान को अलग-अलग समय पर मिला था। UAE ने 2018 में 2 अरब डॉलर का लोन दिया था, जिसे बार-बार बढ़ाया गया। 2023 में 1 अरब डॉलर और दिया गया था, ताकि पाकिस्तान IMF की शर्तें पूरी कर सके।

महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क हादसा, 11 की मौत

एजेंसी, ठाणे (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार को सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। दो गंभीर घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10:45 बजे मुर्बाड के गोविली गांव स्थित रैता ब्रिज पर हुआ। कल्याण से मुर्बाड जा रही वैन की सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं, अन्य दो लोग घायल हैं, जिन्हें उल्हासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 8 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। अब तक 6 मृतकों की पहचान हो चुकी है, बाकी की पहचान जारी है।

कल्याण से मुरबाड के बीच चलती थी वैन वैन रोजाना की तरह आज सुबह भी पैसेंजर्स को लेकर कल्याण से मुरबाड जा रही थी। वैन में ड्राइवर समेत 12-13 लोग सवार

♦ मृतकों में 3 महिलाएं, 2 की हालत गंभीर, वैन से टकराया सीमेंट मिक्सर ट्रक

थे। इसी दौरान रैता ब्रिज पर सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर से टक्कर हो गई। राहगीरों ने बताया कि दोनों गाड़ियां स्पीड में थीं। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में सवार किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। राहगीरों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

हैदराबादवासी श्रद्धालु ने तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट को दिया एक करोड़ का दान

एजेंसी, हैदराबाद

तिरुपति स्थित भगवान बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर ट्रस्ट को हैदराबाद के एक कारोबारी ने एक करोड़ रुपये का दान दिया है। यह रकम गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों के उपचार में खर्च किया जाएगा।

मंदिर प्रशासन ने एक बयान जारी कर बताया कि हैदराबाद निवासी अल्लूरी वर्मा नामक श्रद्धालु ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् (टीटीडी) से जुड़े श्री वेंकटेश्वर प्राणदान ट्रस्ट को एक करोड़ से अधिक की राशि दान दी है। सोमवार को यह दान डिमांड ड्राफ्ट के रूप में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के रंगनायकुला मंडपम में टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सीएच वेंकैया चौधरी को सौंपा गया। अल्लूरी वर्मा हैदराबाद में रहते हैं और उनकी इस्पात बनाने की कंपनी है। वे एक स्टील कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2001

❑ यह रकम गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों के उपचार में खर्च होगा

में स्थापित श्री वेंकटेश्वर प्राणदान ट्रस्ट का उद्देश्य हृदय, किडनी, मस्तिष्क, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। आंध्रप्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर पूरी दुनिया में तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से मशहूर है।

हादसाः दूल्हे के पिता समेत 6 बारातियों की मौत

एजेंसी, हापुड़

यूपी के हापुड़ में रविवार देर रात 1.30 बजे बारातियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 बारातियों समेत 6 की मौके पर मौत हो गई। 7 गंभीर हैं। बारात गाजियाबाद के डासना से बुलंदशहर के गुलावठी गई थी। बस में कुल 13 बाराती थे। बाकी दूसरी कारों से पीछे आ रहे थे। शादी के बाद वापस लौटते वक्त बस रोड किनारे खड़ी थी। रास्ता काफी सकरा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रोड की ढलान पर पहले बस पलटी, फिर बेकाबू ट्रक भी उस पर पलट गया।

भारी भरकम ट्रक के पलटने पर बस पिचक गई। बस की छत उखड़कर अलग हो गई। बाराती अंदर दब गए। चीख-पुकार मच गई। पीछे आ रहे बारातियों ने पुलिस को सूचना दी। बस के शीशे तोड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। कुछ बाराती इस कदर फंस गए थे कि गाड़ी को गैस कटर से काटकर

उनको रेस्क्यू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा हापुड़ जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर धौलाना थाने में धौलाना-गुलावठी रोड पर हुआ। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया शादी समारोह से लौट रही यात्रियों से भरी एक बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा तेज रफ्तार और अंधेरे की वजह से हुआ। ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई है।

टक्कर लगी तो बस के शीशे टूटे, मैं खुद-ब-खुद उछल कर बाहर आ गयाः बस में सवार नदीम ने बताया- बस रुकी हुई थी। मैं ड्राइवर के बगल में कंडक्टर सीट पर बैठा था। रात में करीब 12:35 बजे जैसे ही ट्रक ने टक्कर मारी, बस के सभी शीशे एक झटके में टूट कर चूर-चूर हो गए। मैं खुद-ब-खुद बस से उछल कर बाहर आ गिरा। सिर पर गहरी चोट आई, पर मेरी जान बच गई। मैं बेहोश हो गया। होश आया तो देखा पूरा ट्रक, बस पर पलटा हुआ था। मेरे परिवार के लोग बीच में दबे चिल्ला रहे थे। तब तक पीछे से अन्य

♦ हापुड़ में बस को टक्कर मारकर उसी पर पलटा ट्रक, 3 दिन बाद बेटी की शादी थी

बाराती आ चुके थे। मैं बस के पीछे कार से था, मरने वाले सभी रिश्तेदार प्रत्यक्षदर्शी चांद कुरैशी ने बताया- मैं भी बारात के साथ था। पर बस के पीछे दूसरी कार से लौट रहा था। बाकी बारातियों की बस रास्ते में खड़ी थी। तभी तेज रफ्तार ट्रक आया और टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक बस पर ही पलट गया। मरने वाले सभी मेरे रिश्तेदार थे। बारात बुलंदशहर के गुलावठी शहर में रविवार रात गाजियाबाद के डासना से आई थी। यहां के पीरखां खतीजा मस्जिद के पास के रहने वाले शेर मोहम्मद की बेटी चाईना (22) की शादी, डासना के दूध पीपल वाले क्षेत्र के रहने वाले कपड़ा व्यापारी जाहिद से हुई। लड़की के पिता शेरमोहम्मद ने बताया कि रात करीब 12:30 गुलावठी से बारात लौट गई थी।

नाव हादसा : यमुना नदी से दो और शव बरामद मृतकों की संख्या 15 हुई, एक की तलाश जारी

एजेंसी, मथुरा

मथुरा जिले में यमुना नदी में पंजाब के श्रद्धालुओं की नाव पलटने के बाद डूब कर मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। सोमवार को बचाव दल ने नदी से दो और शव बरामद किए हैं। अभी भी एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है।

सोमवार को एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान यमुना नदी से दो शव और बरामद किये हैं, जिनमें एक की पहचान पंजाब निवासी यश भल्ला उर्फ युवराज के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार यश भल्ला उन 16 लोगों में शामिल थे, जो नाव पलटने के बाद यमुना के तेज बहाव में लापता हो गए थे। उनका शव केसीघाट के निकट

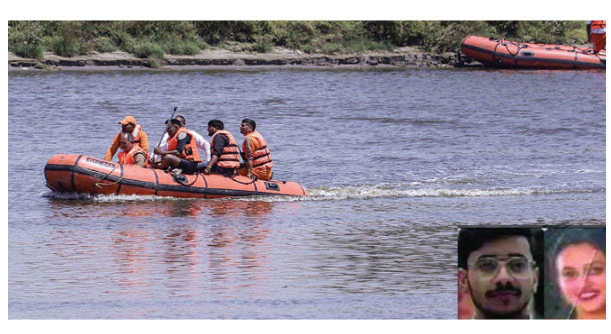

देवराह बाबा घाट के पास झाड़ियों में फंसा मिला।

लंबे समय तक पानी में रहने के कारण शव क्षत-विक्षत अवस्था में था। इसके बाद बचाव दल ने बंगाली घाट के पास से एक युवती का भी शव बरामद कर लिया। जिसकी पहचान मोनिका दुगरी के रूप में हुई है। नाव हादसे में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है।

यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम चला रही है। टीम लगातार यमुना नदी में सर्च अभियान चला रही है और लापता लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बरामद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही सेना की स्ट्राइक वन कोर और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमें इलाके में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अभी एक व्यक्ति और लापता बताया जा रहा है। उसका नाम पंकज है। उसकी खोज के लिए बचाव दल लगातार जुटे हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक देहात सुरेश चन्द्र रावत ने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और निजी गोताखोरों की टीमों को सात सेक्टरों में बांटकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन की मदद से भी नदी और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की जा रही है। फिलहाल एक व्यक्ति अभी भी लापता है, जिसकी तलाश के लिए बचाव दल लगातार अभियान चला रहा है। प्रशासन के अनुसार जब तक लापता व्यक्ति का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा।

ईरान भारतीय जहाजों को होर्मुज पार करने में मदद करेगा

एजेंसी, तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

ईरान ने कहा है कि वह भारत के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने में मदद करेगा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने बताया कि ईरान और भारत के बीच इस मुद्दे पर अच्छी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद ईरान चाहता है कि भारत के जहाज बिना किसी दिक्कत के इस रास्ते से गुजर सकें। इसलिए ईरान, नई दिल्ली की मदद करने के लिए तैयार है।

इससे पहले ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट और उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया गया, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा कि क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा

❑ अमेरिका से कहा- होर्मुज पर हमला किया तो खाड़ी का कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा

सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। सुरक्षा सबके लिए नहीं होगी, तो किसी के लिए भी नहीं होगी। वहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि अमेरिका सोमवार से ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर नाकाबंदी (ब्लॉकेड) लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत ईरान के बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर नजर रखी जाएगी और उन्हें रोका जा सकता है।

बंगाल- सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सवाल उठाए

एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले पर सुनवाई के दौरान गंभीर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि यह राज्य बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई नहीं है। बंगाल का वोटर दोनों के बीच फंसा हुआ है। जस्टिस बागची ने आयोग से कहा- मान लीजिए कि जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके, तो हमें इस पर सोचना होगा। यह चिंता का मामला हो सकता है। यह मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में नहीं है।

हालांकि कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से इनकार कर दिया है जिनके नाम SIR के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनलों में लंबित हैं। कोर्ट ने कहा

कि ऐसा करने से अपीलीय ट्रिब्यूनल पर भारी बोझ पड़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी।

जीत के अंतर से ज्यादा वोटर वोट नहीं डाल पाए तो दखल देंगेः सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम में तभी दखल दिया जाएगा, जब बड़ी संख्या में मतदाता बाहर किए गए हों और वह संख्या जीत के अंतर को प्रभावित करती हो। जस्टिस बागची ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक रिपोर्ट में बताया है कि अपीलीय ट्रिब्यूनलों के पास 34 लाख अपीलें लंबित हैं। चुनाव आयोग ने लंबित मामलों पर सुनवाई के लिए 21 मार्च को 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया था।

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर वेटिकन प्रमुख पोप लियो के रुख की आलोचना की

एजेंसी, वाशिंगटन

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेटिकन प्रमुख पोप लियो (चतुर्दश) की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ईरान युद्ध पर पोप के रुख की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि पोप लियो की विदेश नीति बहुत बुरी है। ट्रंप ने रविवार शाम पत्रकारों से कहा, "हमें ऐसा पोप पसंद नहीं है जो यह कहे कि परमाणु हथियार रखना ठीक है। वह यह नहीं सोचते कि अगर ईरान परमाणु हथियार संपन्न हो गया तो दुनिया को उड़ा देगा।" सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार पहले अमेरिकी पोप और वेटिकन प्रमुख लियो अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध को लेकर लगातार मुखर होते जा रहे हैं। पोप ने पिछले सप्ताह ट्रंप की ईरान को दी गई धमकी की निंदा करते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ट्रंप ने कहा था कि आज रात पूरी सभ्यता मिट जाएगी।यह धमकी ईरान के साथ दो हफ्ते के युद्धविराम पर सहमति बनने से कुछ घंटे पहले आई थी।

ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस संघर्ष के दौरान अपने बयानों में ईश्वर का जिक्र

किया है। हेगसेथ ने तो इस युद्ध को ईश्वरीय समर्थन बताया है और इसके लिए धार्मिक ग्रंथों का भी सहारा लिया है। पोप लियो ने इस विचार का दृढ़ता से विरोध किया है। पोप लियो ने पाम संडे के अवसर पर कहा, ''यीशु शांति के राजा हैं। वो युद्ध को अस्वीकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति युद्ध को सही ठहराने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता।'' इसके बाद ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोप की आलोचना की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, "उन्हें ऐसा कोई पोप नहीं चाहिए जो यह मानता हो कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। और जो यह सोचता हो कि अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला करना एक बेहद खराब कदम था।" ट्रंप ने कहा, "मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे।" राष्ट्रपति ने दावा किया कि लियो में पोप बनने की कोई अहर्ता नहीं थी। उन्हें चर्च ने सिर्फ इसलिए स्वीकार किया, क्योंकि वे अमेरिकी थे। ट्रंप की आलोचना के जवाब में वेटिकन के अधिकारी फादर एंटोनियो स्पडारो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप एक नैतिक आवाज को दबाना चाहते हैं। स्पडारो ने एक्स पर कहा कि लियो से ट्रंप बहस नहीं कर सकते। पोप लियो के शब्दों का गहरा असर होता है। इसलिए ट्रंप बेचैन हो जाते हैं। पोप लियो पहले भी परमाणु हथियारों के बढ़ते प्रसार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। पिछले जून में जब ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने पर विचार कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था, "परमाणु खतरे से मुक्त एक सुरक्षित दुनिया बनाने के संकल्प को आपसी सम्मान और सच्ची बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि न्याय, भाईचारे और सबके भले पर आधारित एक स्थायी शांति स्थापित की जा सके।" इस विवाद पर व्हाइट हाउस ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023- वंशवाद और प्रॉक्सी नेतृत्व दोनों को बढ़ावा?अयोग्यता, जुर्माना और कारावास जैसी सख़्त सजा का प्रावधान ज़रूरी?-प्रतिनिधित्व से वास्तविक नेतृत्व तक-एक अधूरा सफ़र और आवश्यक सुधारों की आवश्यकता

लोकतंत्र की शान

गोंदिया -वैश्विक स्तरपर भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023(106वां संशोधन) (महिला आरक्षण विधेयक) भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है महिलाओं को लोकसभा और राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर नीति- निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है।आलोचकों का मानना है कि इससे प्रॉक्सी नेतृत्व (पति/पिता के नाम पर महिला प्रतिनिधि)और वंशवाद/ भाई-भतीजावाद बढ़ सकता है, जबकि समर्थक इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम मानते हैं।आलोचक तर्क देते हैं कि ग्रामीण या जमीनी स्तरपर पुरुष नेता अपनी पत्नियों या बेटियों को उम्मीदवार बनाकर पर्दे के पीछे से शासन कर सकते हैं।यह भी आशंका जताई जा रही है कि पहले से स्थापित राजनीतिक परिवार अपनी महिला सदस्यों को सीटें दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहूंगा क़ि वैसे ग्रामीण स्तरपर प्रॉक्सी सरपंच के ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है वैसा ही नियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में भी बनाना जरूरी है।13 अप्रैल 2026 को पीएम ने राष्ट्रीय स्तर के महिला सम्मेलन में

» क्या हम केवल महिला नेतृत्व संख्या बढ़ाना चाहते हैं?या वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं? यही प्रश्न आज संसद के सामने है,और यही इस अधिनियम की वास्तविक परीक्षा भी

» क़्या चुनी हुई महिला प्रतिनिधि केवल एक औपचारिक चेहरा बनकर रह जाती हैं?जबकि वास्तविक निर्णय व नेतृत्व उनके पति, पिता,भाई या अन्य पुरुष रिश्तेदार लेते हैं? संसद ने इसपर सख़्त संज्ञान लेना समय की मांग -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

कहा कि लोकतंत्र में महिला आरक्षण अति आवश्यक है महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है,मैं अत्यंत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है,यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है,नारी शक्ति वंदन को समर्पित हैं।बता दें दशकों से लंबित इस मांग को संवैधानिक स्वरूप देकर यह अधिनियम महिलाओं को विधायिका में समान भागीदारी की दिशा में आगे बढ़ाता है।किंतु इस ऐतिहासिक पहल के साथ- साथ कई जमीनी चुनौतियां और संरचनात्मक समस्याएं भी सामने आती हैं,जिनका समाधान किए बिना यह आरक्षण केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित रह सकता है,वास्तविक नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाएगा? यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क़्या इस अधिनियम से वंशवाद तथा प्रॉक्सी नेतृत्व शुरू नहीं हो जाएगा? क्या केवल आरक्षण देने से महिलाओं का वास्तविक नेतृत्व सुनिश्चित हो

जाएगा?भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के अनुभव बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। अनेक मामलों में चुनी हुई महिला प्रतिनिधि केवल एक औपचारिक चेहरा बनकर रह जाती हैं,जबकि वास्तविक निर्णय उनके पति, पिता,भाई या अन्य पुरुष रिश्तेदार लेते हैं। इस प्रवृत्ति को आम भाषा में सरपंच पति या प्रॉक्सी नेतृत्व कहा जाता है। यह समस्या केवल पंचायत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी देखने को मिलती है।यह स्थिति लोकतंत्र की मूल भावना जनता द्वारा,जनता के लिए,जनता का शासन के साथ एक प्रकार का समझौता है।जब एक महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र की होती है और वास्तविक सत्ता किसी और के हाथ में होती है, तब यह न केवल महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को विफल करता है,बल्कि मतदाताओं के विश्वास के साथ भी धोखा है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं जो इस प्रॉक्सी नेतृत्व को रोक सकें। 16 से 18 अप्रैल 2026 को होने वाले संसद के विशेष सत्र में भाग लेने वाले सांसदों का ध्यान मैं इस आर्टिकल के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस विषय पर संज्ञान लेकर संसद में विचार विमर्श करें ऐसा मेरा निवेदन है? साथियों बात अगर हम सरकार द्वारा उठाए गए सरपंच पति के खिलाफ़ एक्शन की करें तो ज़मीनी स्तरपर लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए एक अहम कदम के तौर पर,पंचायती राज मंत्रालय ने प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें कैंपेन शुरू किया है।इंटरनेशनल महिला दिवस 2026 पर शुरू की गई इस देशव्यापी पहल का मकसद सरपंच पति कल्चर को खत्म करना है,जो बहुत गहराई तक जड़ें जमा चुका है और यह पक्का करना है कि चुनी हुई महिला प्रतिनिधि अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल आज़ादी से करें। सरपंच पति या प्रधान पति उस प्रथा को कहते हैं जिसमें चुनी हुई महिला सरपंच का पति या पुरुष रिश्तेदार असल में एडमिनिस्ट्रेटिव और फ़ैसले लेने की पावर रखता है, जिससे महिला सिर्फ़ केवल नाममात्र की ही मुखिया बनकर रह जाती है जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथियों बात अगर हम महिलाओं को सशक्त बनाने वास्तविक नेतृत्व देने का अपना उद्देश्य सफल बनाने की करें तो मेरे विचार से इन पांच रणनीतियों पर संज्ञान लेने की सख़्त जरूरत है,सबसे पहली रणनीति यह होसकती है कि कानून में स्पष्ट रूप से प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की परिभाषा दी जाए और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। यदि यह प्रमाणित हो कि किसी महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है,जैसे कि बैठकों में

भाग लेना, निर्णय लेना,दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, सीक्रेट दस्तावे देखना चुनीं हुई प्रतिनिधि के सिवाय उसका पति या कोई रिश्तेदार कर रहा है तो तो उस स्थिति में संबंधित व्यक्ति और महिला प्रतिनिधि दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। इसके तहत पद से अयोग्यता, जुर्माना और कारावास जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जा सकता है।दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है,क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग)। केवल सीट आरक्षित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक,विधायी और वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरपर विशेष प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं,जहां महिलाओं को नेतृत्व कौशल,निर्णय लेने की क्षमता और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी जाए। यदि महिलाएं आत्मविश्वास और ज्ञान से सशक्त होंगी, तो वे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगी।तीसरी रणनीति के रूप में डिजिटल पारदर्शिता और निगरानी तंत्र कोमजबूत किया जाना चाहिए। आज के डिजिटल युग में यह संभव है कि सभी सरकारी बैठकों,निर्णयों और फंड के उपयोग को ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाए।यदि किसी बैठक में महिला प्रतिनिधि की जगह कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित होता है या निर्णय लेता है,तो इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसके साथ ही,नागरिकों को भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे वे किसी भी प्रकार के प्रॉक्सी नेतृत्व की सूचना संबंधित प्राधिकरण को दे सकें।चौथी रणनीति है,राजनीतिक दलों की जवाबदेही।अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक दल सुरक्षित सीटों पर अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अपने परिवार की महिलाओं को उम्मीदवार बना देते हैं। इससे वंशवाद और प्रॉक्सी नेतृत्व दोनों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों के लिए भी आचार संहिता बनाई जाए,जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि उम्मीदवारों का चयन केवल पारिवारिक संबंधों के आधार पर न हो,बल्कि उनकी योग्यता,अनुभव और सामाजिक योगदान को प्राथमिकता दी जाए।पांचवीं और अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीति है,सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन। कानून केवल एक ढांचा प्रदान कर सकता है, लेकिन वास्तविक बदलाव समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन से ही आएगा।जब तक समाज महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने वाली नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेगा,तब तक किसी भी कानून का प्रभाव सीमित रहेगा। इसके लिए शिक्षा, मीडिया और सामाजिक अभियानों के माध्यम से यह संदेश फैलाना होगा कि महिला नेतृत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक और प्रभावी होना चाहिए। साथियों हम इस बात पर विचार करें कि अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या एक सक्षम और तेजस्वी महिला नेता बिना किसी पुरुष हस्तक्षेप के राजनीति में टिक पाएगी? इसका उत्तर है,हाँ, लेकिन इसके लिए एक सहायक पारिस्थितिकी की आवश्यकता है। यदि कानून मजबूत हो, प्रशिक्षण उपलब्ध हो, और समाज का समर्थन मिले, तो महिलाएं न केवल टिकेंगी बल्कि उत्कृष्ट नेतृत्व भी प्रदान करेंगी। भारत में पहले से ही कई उदाहरण हैं,जहां महिलाओं ने अपने दम पर राजनीति में अपनी पहचान बनाई है और प्रभावी निर्णय लिए हैं। साथियों बात अगर हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गहराई से समझने की करें तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इस अधिनियम के तहत महिलाओं को किन- किन चुनावों में 33.33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस कानून के अनुसार, भारत की संसद (लोकसभा) और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत उप- आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। हालांकि यह आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा, बल्कि इसके लागू होने की शर्तें निर्धारित की गई हैं पहली देश में अगली जनगणना पूरी हो; दूसरी, उसके आधार पर परिसीमन (डेलिमिटेशन) की प्रक्रिया पूरी की जाए।अनुमानत यह प्रक्रिया 2029 के आम चुनावों तक पूरी हो सकती है, जिसके बाद यह आरक्षण प्रभावी रूप से लागू होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिनियम स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर निकायों) पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पहले से ही 33 प्रतिशत से लेकर कई राज्यों में 50 प्रतिशत तक महिला आरक्षण लागू है। अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि 16 से 18 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित विशेष संसद सत्र केवल आरक्षण लागू करने का अवसर नहीं है, बल्कि इसे सार्थक और प्रभावी बनाने का भी एक ऐतिहासिक मौका है। संसद के माननीय सदस्यों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि यदि इस अधिनियम में प्रॉक्सी नेतृत्व को रोकने के लिए ठोस प्रावधान नहीं जोड़े गए, तो यह कानून अपने मूल उद्देश्य से भटक सकता है।इसलिए यह समय की मांग है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को केवल एक आरक्षण कानून के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक- राजनीतिक सुधार के रूप में विकसित किया जाए।इसमें कानूनी दंड,प्रशिक्षण,पारदर्शिता राजनीतिक जवाबदेही और सामाजिक परिवर्तन इन सभी पहलुओं को शामिल करना आवश्यक है।तभी यह अधिनियम भारत की महिलाओं को केवल सीट ही नहीं, बल्कि सत्ता और सम्मान भी दिला सकेगा।इस ऐतिहासिक मोड़ पर लिया गया निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा निर्धारित करेगा क्या हम केवल संख्या बढ़ाना चाहते हैं, या वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं? यही प्रश्न आज संसद के सामने है, और यही इस अधिनियम की वास्तविक परीक्षा भी।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9284141425

बाबासाहेब के प्रति नेहरू-गांधी का शत्रुता भाव

लेखक- डॉ. प्रवीण दाताराम गुगनानी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद यदि, स्वतंत्र भारत की राजनीति व समाज को किसी ने सर्वाधिक प्रभावित किया है वे हैं पहले गांधी जी व दूजे अंबेडकर जी। कांग्रेस द्वारा बाबासाहेब की घोर उपेक्षा के बाद भी भारतीय राजनीति में उनकी लगातार बढ़ती स्वीकार्यता का इतिहास पढ़ना हो तो एक और व्यक्ति का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। वे हैं जोगेंद्रनाथ मंडल। कांग्रेस की सतत उपेक्षा के शिकार जोगेंद्रनाथ मंडल ने यदि स्वतंत्रता पूर्व की भारतीय राजनीति में बाबासाहेब को सफलतापूर्वक स्थापित न किया होता तो आज भारत में दलित चिंतन का स्वरूप आमूलचूल भिन्न होता। प्रारंभ से ही दलित चिंतन को उपेक्षा की दृष्टि से देखने वाली कांग्रेस ने जब बाबासाहेब के प्रति बेहद अपमानजनक रवैया अपनाते हुये संविधान सभा में भेजे गए प्रारंभिक 296 सदस्यों में अंबेडकर को जगह नहीं दी थी तब जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंबेडकर जी को संविधान सभा में भेजने की भूमिका बनाई थी। जब कांग्रेस ने संविधान सभा में अंबेडकर जी के प्रवेश को रोकने हेतु प्रपंच प्रारंभ किये तब मंडल ने बंगाल के खुलना-जैसोर से अपनी सीट खाली करके बाबासाहेब को संविधान सभा में भेजा था। विभाजन में यह तय हुआ था कि जिन क्षेत्रों में हिंदू जनसंख्या 51% से अधिक है वे क्षेत्र भारत में रहेंगे। इसके बाद भी कांग्रेस ने तब हद दर्जे की गलती करते हुये बाबा साहेब को संविधान सभा में षड़यंत्रपूर्वक अप्रासंगिक करने हेतु बंगाल के खुलना-जैसोर को 71% हिंदू बहुल वाला क्षेत्र होने के बाद भी पाकिस्तान को सौंप दिया और तब बाबासाहेब तकनीकी तौर पर पाकिस्तानी संविधान सभा के सदस्य माने गये थे। बाबासाहेब ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से बाबासाहेब बंबई राज्य से एमएस जयकर द्वारा खाली की गई सीट से चुनकर भारतीय संविधान सभा में पहुंच पाये थे।

बाबासाहेब प्रारंभ से ही अखंड भारत के पक्ष में थे। उन्होंने बंटवारे के लिए एक पैर पर तैयार और तत्पर गांधीजी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जिन्ना का भी पुरजोर विरोध किया। उनकी पुस्तक "थॉट्स ऑन पाकिस्तान" में इसका पूरा विवरण है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के चलते कांग्रेस ने देश का बंटवारा कर डाला। बाबासाहेब की स्पष्ट मान्यता थी कि जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हो चुका है, तब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत आ जाना चाहिए। उन्होंने यह यह भी आशंका जताई थी कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे से हिंदुओं को गंभीर क्षति पहुंचेगी और ऐसा हुआ भी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बचे ज्यादातर दलित या तो मार डाले गए या फिर उनसे बलात् धर्म परिवर्तन कराया गया। तब जोगेन्द्रनाथ मंडल अपनी ही हुकूमत में चीखते-चिल्लाते रह गए थे। तब न पाकिस्तान सरकार न भारत की नेहरू सरकार ने दलित हिंदुओं की मदद की थी। इस प्रकार देश में प्रथम मुस्लिम-दलित राजनीति का प्रयोग हुआ जो कि बेहद असफल व निराशाजनक रहा किंतु यह प्रयोग अब भी यदा कदा यहां-वहां 'भीम मीम' नाम से प्रयुक्त होता रहता है। बाबा साहेब और सुभाषचंद्र बोस के प्रति गांधी जी का व्यवहार उनके उपनाम 'महात्मा' शब्द के अनुरूप कतई नहीं था। वर्ष 2013 में प्रकाशित पुस्तक "डॉ. बाबा साहब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस" के 17वें खंड के पृष्ठ संख्या 366 से 369 बड़े ही उल्लेखनीय हैं। 27 नवंबर, 1947 को बाबासाहेब ने लिखा कि 'मुझे पाकिस्तान और हैदराबाद की अनुसूचित जातियों के लोगों की ओर से असंख्य शिकायतें मिल रही हैं और अनुरोध किया जा रहा है कि उनको दुख और परेशानी से निकालने के लिए मैं कुछ करूं। पाकिस्तान से उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है और जबरन उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है। हैदराबाद में भी उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, ताकि मुस्लिम आबादी की ताकत बढ़ाई जाए।'

संविधान और कला का अंतर्संबंध: 'सम' की साधना और सामाजिक सामंजस्य

लोकतंत्र की शान

भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज या कानूनों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा और सामूहिक चेतना का कलात्मक घोषणापत्र है। 'संविधान' शब्द का शाब्दिक विश्लेषण करें तो इसका अर्थ 'सम का विधान' निकलता है—अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जो विषमताओं को समाप्त कर सबको समानता के धरातल पर खड़ा करे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक न्याय की अवधारणा एक ऐसे कलात्मक और सभ्य समाज का आदर्श प्रस्तुत करती है, जहाँ भेदभाव का कोई स्थान न हो। यह एक ऐसा 'साध्य' है जिसे प्राप्त करना जितना अनिवार्य है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। वैश्विक स्तर पर देखें तो आज भी पूर्ण समानता का यह लक्ष्य एक स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। यदि वास्तव में इस 'सम' यानी पूर्ण समानता को हासिल कर लिया जाता, तो शायद हमें इतने विस्तृत पुलिस तंत्र और अदालतों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समता की राह पर चलना हमारा सर्वोच्च नैतिक उत्तरदायित्व है, किंतु व्यावहारिक रूप से हम अक्सर श्रेष्ठता के मिथ्या अहंकार में डूबे रहते हैं। जैसे ही अवसर मिलता है, मनुष्य 'सम' को छोड़कर 'विशिष्ट' या 'विषम' होने की चेष्टा करने लगता है। आधुनिक सभ्यता, बाजार और सत्ता की राजनीति अक्सर इसी भेदभाव और 'हम सबसे श्रेष्ठ' के नारे पर टिकी होती है, जो संविधान के मूल दर्शन के ठीक विपरीत है। कला के संसार में 'सम' की अवधारणा अत्यंत पवित्र और अनिवार्य मानी जाती है। संगीत, नृत्य, नाटक और चित्रकला में जब तक 'सम' का भाव हासिल नहीं होता, तब तक रचना अपूर्ण और निष्प्राण रहती है। संगीत में ताल की वह अंतिम बिंदु जहाँ गायक, वादक और नर्तक एक साथ मिलते हैं, वही 'सम' है। यदि कलाकार इस बिंदु को चूक जाए, तो न केवल उसकी तकनीकी दक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगता है, बल्कि रसिक उपभोक्ता भी 'रसभंग' की पीड़ा से भर जाता है। एक कलाकार के लिए 'बेसुरा' या 'बेताला' कहलाना सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि यह उसकी बरसों की साधना और निष्ठा की विफलता को दर्शाता है। साहित्यकार भी अपनी रचनाओं में इसी 'सम' को साधने का प्रयास करते हैं, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच पूर्ण सामंजस्य हो। कला हमें सिखाती है कि विषमता केवल एक 'विषय' हो सकती है ताकि उसकी कमियों को उजागर किया जा सके, लेकिन वह कला का 'हासिल' या अंतिम लक्ष्य कभी नहीं हो सकती। जिस प्रकार कला में एक भी अपशब्द या गलत स्वर पूरे आनंद को विषाक्त कर देता है, वैसे ही समाज के सौहार्द में हिंसा, युद्ध या घृणा का एक भी स्वर 'सम' के आनंद में रसभंग कर देता है। भारत के सांस्कृतिक पर्यावरण में कलाकारों की भूमिका एक जीवंत सेतु की तरह है। एक अनुमान के अनुसार, देश में लगभग दो करोड़ पेशेवर कलाकार हैं, लेकिन यदि हम हर घर और गली में तीज-त्योहारों पर अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति करने वाले शौकिया कलाकारों और रसिकों को जोड़ लें, तो यह संख्या अनगिनत हो जाती है। ये कलाकार और रसिक भारत की 'सांस्कृतिक रीढ़' हैं। संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 इन्हीं विविध समुदायों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कलाकार चाहे शास्त्रीय विधा का हो या लोक विधा का, संविधान की दृष्टि में सबका योगदान राष्ट्र की एकता के लिए समान रूप से अमूल्य है। गली-मोहल्लों में होने वाले सामूहिक सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में उन्हीं संवैधानिक मूल्यों का उत्सव हैं, जहाँ विविधता को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक शक्ति के रूप में देखा जाता है। ये आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि कला और कलाकार समाज के उस ढांचे में रंग भरने का काम करते हैं जिसे संविधान ने तैयार किया है। एक कलाकार की प्रदर्श-कला की यात्रा वास्तव में संविधान की भावना का व्यावहारिक प्रदर्शन है। जब एक मुख्य कलाकार अपने साथ विभिन्न साज-बाज और गायन के सहयोगियों को लेकर मंच पर उतरता है, तो वे सभी अपनी व्यक्तिगत पहचान, धर्म, जाति और संप्रदाय को विस्मृत कर देते हैं। मंच पर उनका एकमात्र धर्म 'सत्यम शिवम सुंदरम' की प्राप्ति होता है। हारमोनियम, तबला, सारंगी और तानपुरा—सबकी अपनी विशिष्ट ध्वनि और पहचान होती है, लेकिन उनकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब वे एक-दूसरे के पूरक बनकर 'हिलमिल' कर चलते हैं। यह 'हिलमिल' कर खेलना और अंततः एक साथ 'सम' पर पहुँचना ही वह स्थिति है जहाँ कलाकार और प्रेक्षक दोनों आनंद के सागर में सराबोर हो जाते हैं। यही प्रक्रिया एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी अनिवार्य है। समाज जब अपनी विविधताओं को भेदभाव का कारण बनाने के बजाय उन्हें सामूहिक सौंदर्य का हिस्सा बना लेता है, तब वह वास्तविक अर्थों में संवैधानिक 'सम' को प्राप्त करता है।

अंततः, संविधान और कला दोनों का चरम लक्ष्य मानवता का कल्याण और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है। कलाकारों की यह विशाल संख्या केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज की चेतना को जागृत कर उसे अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने का माध्यम है। यदि हम संविधान द्वारा दिखाए गए 'सम' के मार्ग पर कलात्मक निष्ठा के साथ चलें, तो विषमताओं का अंत संभव है। जिस प्रकार एक कुशल गायक कठिन से कठिन आलाप के बाद वापस 'सम' पर आकर शांति और संतोष प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र के रूप में हमें भी अपनी तमाम राजनीतिक और सामाजिक उठापटक के बाद अंततः संवैधानिक मूल्यों के 'सम' पर ही लौटना होगा। यही वह बिंदु है जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक हित का संगम होता है। अतः, कलाकारों की साधना और संविधान का दर्शन मिलकर एक ऐसे भारत का मार्ग प्रशस्त करते हैं जहाँ समता केवल एक कानूनी अधिकार न होकर, हमारे जीवन का सहज रस और संस्कार बन जाए।

सामाजिक न्याय एवं समानता के पुरोधा पुरुष थे डॉ. अंबेडकर

लेखक- ललित गर्ग

आधुनिक भारत के निर्माण की जब भी चर्चा होती है, तो डॉ. भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व एक ऐसे विराट स्तंभ के रूप में सामने आता है, जिसने न केवल संविधान की रचना की, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा को समता, न्याय और मानवीय गरिमा के मूल्यों से अनुप्राणित किया। डॉ. अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद्, बहु-भाषाविद्, धर्म-दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया। निश्चित ही वे केवल एक विधिवेत्ता या राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी चिंतक थे, जिन्होंने भारतीय समाज की गहराई में पैठे जातिगत अन्याय, सामाजिक विषमता और आर्थिक शोषण को समझा और उसके समाधान के लिए ठोस वैचारिक एवं संस्थागत आधार प्रदान किया। आज "नया भारत", "विकसित भारत" और "समृद्ध भारत" की जो अवधारणा हमारे सामने है, उसकी जड़ें अंबेडकर की सोच, नीतियों और संविधान में निहित हैं। डॉ. अंबेडकर का जीवन स्वयं में एक संघर्षगाथा है। एक अस्पृश्य माने जाने वाले परिवार में जन्म लेकर उन्होंने जो अपमान, भेदभाव और पीड़ा झेली, वही उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प बनकर उभरी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि प्रतिभा किसी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं होती। उनका यह विश्वास कि "शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो" केवल एक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का सूत्र था। अंबेडकर के चिंतन का मूल आधार "सामाजिक न्याय" था। उनका स्पष्ट मत था कि जब तक समाज में समता स्थापित नहीं होती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। वे मानते थे कि केवल आर्थिक विकास से सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, बल्कि इसके लिए सामाजिक संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन आवश्यक है। इसी दृष्टि से उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज का सबसे बड़ा शत्रु माना और उसके उन्मूलन के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी प्रसिद्ध कृति "जाति का विनाश" में उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति केवल सामाजिक विभाजन नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ एक सुनियोजित अन्याय है। भारतीय संविधान के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका उनकी दूरदर्शिता और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण है। संविधान में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों को इस प्रकार समाहित किया कि यह दस्तावेज न केवल शासन का आधार बना, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बना। मौलिक अधिकारों, विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 17), आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान उनके उस दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसमें हर नागरिक को समान अवसर और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो। डॉ. अंबेडकर का "संवैधानिक नैतिकता" का सिद्धांत आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनका मानना था कि केवल संविधान बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके मूल्यों को समाज और शासन दोनों में आत्मसात करना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बनी रहीं, तो राजनीतिक लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। आज जब भारत विविधताओं से भरे समाज के रूप में आगे बढ़ रहा है, तब यह सिद्धांत हमें संतुलन और समन्वय की दिशा दिखाता है। अंबेडकर केवल सामाजिक सुधारक ही नहीं, बल्कि एक प्रखर आर्थिक चिंतक भी थे। उन्होंने औद्योगीकरण, श्रमिक अधिकारों, जल संसाधन प्रबंधन और वित्तीय विकेंद्रीकरण जैसे विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए। भारतीय रिजर्व बैंक की अवधारणा से लेकर श्रम कानूनों के निर्माण तक उनके विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे मानते थे कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है, इसलिए उन्होंने दलितों और वंचितों को केवल सामाजिक सम्मान ही नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी प्रेरित किया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी अंबेडकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, विवाह और तलाक में समानता दिलाने का प्रयास किया। यद्यपि तत्कालीन परिस्थितियों में इस विधेयक को पूर्ण रूप से पारित नहीं किया जा सका, लेकिन उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में लैंगिक समानता की नींव रखी। आज भारतीय महिलाएं जो अधिकार और स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हैं, उसमें अंबेडकर की दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण योगदान है।

धार्मिक दृष्टि से भी अंबेडकर का चिंतन अत्यंत गहन और मानवीय था। उन्होंने धर्म को आस्था का नहीं, बल्कि नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का विषय माना। 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर उन्होंने यह संदेश दिया कि धर्म वह होना चाहिए जो मानव को समानता, करुणा और विवेक की ओर ले जाए। उनका यह कदम केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। समकालीन भारत में अंबेडकर की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। जब हम डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की बात करते हैं, तो यह आवश्यक है कि इन पहलों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अंबेडकर का "समावेशी विकास" का दृष्टिकोण हमें यही सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है, जब उसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो। आज भी यदि कहीं सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता या अवसरों की विषमता दिखाई देती है।

कोहली ने बाबर-गेल का रिकॉर्ड तोड़ा

- **रोहित ने मुंबई के लिए 6 हजार रन पूरे किए, पाटीदार की आरसीबी के लिए सेकेंड फास्टेस्ट फिफ्टी**

बेंगलुरु (एजेंसी)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को विराट कोहली टी-20 में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां करने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने बाबर आजम और क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। मैच में रोहित शर्मा ने भी खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 6000 रन पूरे किए। रजत पाटीदार ने 17 गेंदों में फिफ्टी लगाकर आरसीबी के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाया और गेल की बराबरी की।

बेंगलुरु ने लगातार चौथी बार 200+ स्कोर बनाया- आरसीबी ने आईपीएल 2026 में लगातार चौथी बार 200+ स्कोर बनाया। लगातार सबसे ज्यादा 200+ स्कोर का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद (5 बार, 2025-26) के नाम है। पंजाब किंग्स (2023) और बेंगलुरु (2024) ने 4-4 बार यह किया था।

पाटीदार ने क्रिस गेल की बराबरी की- रजत पाटीदार ने 17 गेंदों में फिफ्टी लगाकर आरसीबी के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाया। उन्होंने क्रिस गेल की बराबरी की, जिन्होंने 2013 में 17 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी। इस लिस्ट में टॉप पर रोमारियो शेफर्ड हैं, जिन्होंने 2025 में 14 गेंदों में यह किया था।

कोहली ने मुंबई के खिलाफ 7वां 50+ स्कोर बनाया

विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सातवां 50+ स्कोर बनाकर सुरेश रैना और डेविड वॉर्नर की बराबरी की। इस लिस्ट में टॉप पर केएल राहुल हैं, जिनके नाम 9 स्कोर हैं। कोहली ने वानखेड़े में अपने टी-20 करियर का 9वां 50+ स्कोर 23 मैचों में पूरा किया।

कोहली ने 47वीं बार शतकीय साझेदारी की

विराट कोहली टी-20 में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां करने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने पहले विकेट के लिए फिल सॉल्ट के साथ 120 रन जोड़े। यह कोहली की 47वीं साझेदारी थी। उन्होंने बाबर आजम और क्रिस गेल (46-46) को पीछे छोड़ा।

रोहित ने मुंबई के लिए 6 हजार रन पूरे किए

रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए 6000 रन पूरे किए। इस लिस्ट में टॉप पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने आरसीबी के लिए 8800+ रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी और चौथे पर सुरेश रैना हैं, जिन्होंने चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी गई

पिट्टू प्रतियोगिता में छाई पौड़ी की लड़कियां, रुद्रप्रयाग के लड़के

रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ समापन

देहरादून (एजेंसी)। राजधानी के जीआरडी गर्ल्स डिग्री कॉलेज (प्रेमनगर) में चल रही 'प्रथम राज्य स्तरीय जूनियर बालक-बालिका पिट्टू प्रतियोगिता' का रविवार को समापन हुआ। देहरादून

- **फाइनल मुकाबले में पौड़ी की बालिकाओं ने रुद्रप्रयाग को हराया**

पिट्टू एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में पौड़ी की लड़कियों और रुद्रप्रयाग के लड़कों ने अपना दबदबा कायम करते हुए चैंपियन का ताज पहना। वहीं, बालिका वर्ग में उत्तरकाशी और बालक वर्ग में मेजबान देहरादून ने तीसरा स्थान हासिल किया। रविवार को खेले गए

सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया और दर्शकों को कई रोमांचक मैच देखने को मिले।

- **बालक वर्ग में भी टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली-** पहले सेमीफाइनल में रुद्रप्रयाग ने उत्तरकाशी को 80-67 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पौड़ी ने देहरादून को 127-48 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। मेजबान देहरादून ने तीसरे मुकाबले में उत्तरकाशी को 58-42 से हराकर तीसरा स्थान सुनिश्चित किया। जबकि खिताबी मुकाबले में रुद्रप्रयाग के खिलाड़ियों ने रणनीति के तहत खेलते हुए पौड़ी को 75-67 से मात दी और चैंपियन बन गए।

बालिका वर्ग के फाइनल में पौड़ी ने रुद्रप्रयाग को 99-63 से हराया

बालिका वर्ग में पौड़ी का एकतरफा दबदबा रहा और खिताबी सफर में टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। दिन के पहले सेमीफाइनल में रुद्रप्रयाग ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में उत्तरकाशी को 49-44 से हराया। वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में पौड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देहरादून को 133-39 के बड़े अंतर से एकतरफा शिकस्त दी।

तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उत्तरकाशी ने देहरादून को 56-40 से हराकर बाजी मारी। जबकि खिताबी मुकाबले में पौड़ी की बालिकाओं का दबदबा कायम रहा और उन्होंने रुद्रप्रयाग को 99-63 से हराकर राज्य स्तरीय ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया।

विजेताओं को किया गया सम्मानित

प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के प्रतिनिधि राय सिंह नेगी, उत्तराखंड पिट्टू एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद पांडे और सचिव अश्वनी भट्ट ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरित कर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर जीआरडी कॉलेज के निदेशक सिद्धांत चमोली, प्राचार्या प्रियंका सिंह, सुशील चमोली, देहरादून पिट्टू एसोसिएशन के सचिव विनोद पंवार, शशांक उनियाल, ओम प्रकाश, जितेंद्र लिंगवाल, मुकेश और संध्या थापा समेत कई खेल प्रेमी व गणमान्य लोग मौजूद रहे।

आयुष शेट्टी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता

फाइनल में चीनी खिलाड़ी से हारे, 60 साल बाद कोई भारतीय खिताबी मुकाबला खेल रहा था

झेजियांग (एजेंसी)। भारतीय शटलर आयुष शेट्टी को बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में उन्हें चीन के शी यू की के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

60 सालों के बाद किसी भारतीय ने चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स कैटेगरी के फाइनल में जगह बनाई थी। आयुष से पहले दिनेश खन्ना ने 1965 में मेंस सिंगल्स में गोल्ड जीता था।

रविवार को चीन के झेजियांग में खेले गए फाइनल में आयुष का मुकाबला दुनिया के नंबर-2 खिलाड़ी शी यू की से था। 20 साल के आयुष यह मैच 8-21, 10-21 से सीधे गेम में हार गए।

सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय- इस हार के बावजूद आयुष ने अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मेंस शटलर बन गए हैं। इससे पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था। खन्ना के बाद फाइनल तक का सफर तय करने वाले आयुष पहले भारतीय खिलाड़ी हैं।

टूर्नामेंट में भारत का 19वां मेडल

बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 1962 से खेली जा रही है। टूर्नामेंट में यह भारत का कुल 19वां मेडल है। भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 1 सिल्वर (आयुष) और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 1965 में दिनेश खन्ना ने सिंगल्स में और 2023 में सात्विक-चिराग की जोड़ी ने मेंस डबल्स में गोल्ड जीता था।

सेमीफीइनल में डिफेंडिंग चैंपियन को हराया

इस पूरे टूर्नामेंट में आयुष का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 4 और वर्ल्ड नंबर 7 जैसे टॉप रैंक वाले खिलाड़ियों को हराया था। शनिवार को हुए सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-25 आयुष ने डिफेंडिंग चैंपियन और नंबर-1 प्लेयर कुन्लावत वितिदसर्न को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी।

रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर के साथ दिखे अर्शदीप सिंह

वायरल हुआ यह क्यूट वीडियो

मुंबई (एजेंसी)। पंजाब किंग्स के स्टार खिलाड़ी अर्शदीप सिंह इन दिनों अपनी गेंदबाजी की वजह से नहीं, बल्कि निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। अर्शदीप ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर फोटो शेयर की थी। उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर अर्शदीप की गर्लफ्रेंड है कौन! इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने दावा किया कि पंजाबी अभिनेत्री और मॉडल समरीन कौर ही अर्शदीप की गर्लफ्रेंड हैं। अब अर्शदीप आईपीएल 2026 के दौरान अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन के साथ स्पॉट भी हुए हैं। दोनों एक साथ नजर आए और क्यूट पल बिताते दिखे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

अर्शदीप ने साझा की थी तस्वीर- अर्शदीप का हाल ही में स्नैपचैट वीडियो वायरल हुआ था।

टीम ट्रैवल के दौरान का वीडियो

वीडियो आईपीएल के दौरान का ही, क्योंकि अर्शदीप के पीछे पंजाब की टीम बस खड़ी दिख रही है। अर्शदीप भी सामान के साथ हैं, यानी वीडियो टीम ट्रैवल के दौरान की है। अर्शदीप के साथ समरीन खड़ी हैं और अर्शदीप कुछ क्यूट से जेस्चर बनाते हैं और समरीन उस पर हंसने लगती हैं। इसके बाद समरीन से मिलने कोई महिला आती है और समरीन उनसे गले मिलती दिखती हैं।

व्यापार

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरान-अमेरिका युद्ध के बढ़ते तनाव और पाकिस्तान में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने से आज सुबह के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। एमसीएक्स पर सोने का भाव आज 1,51,547 रुपये प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर खुला और कुछ ही मिनटों में 1,51,457 रुपये प्रति 10 ग्राम के को छू गया। जबकि, एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 2.5 प्रतिशत गिरकर 2,37,190 रुपये प्रति किलोग्राम पर आग गई। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4,723.55 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी भी यहां दो प्रतिशत टूटकर 74.36 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। यूनियन बैंक प्रिवी के एशिया में प्रमुख परास गुप्ता का कहना है कि वीकेंड की घटनाओं ने नाजुक सीजफायर को खतरे में डाल दिया है। और संभवत: युद्ध को लंबा खींच देंगे। हालांकि, सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव युद्ध की शुरुआत की तुलना में अब कम है, लेकिन असली परीक्षा सोमवार को लंदन के बाजार खुलने पर होगी। एनरिच मनी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने की कीमतें 1,48,000 रुपये से 1,46,000 रुपये के सपोर्ट बैंड से ऊपर बनी हुई हैं। इस जोन से नीचे की गिरावट 1,40,000 रुपये से 1,36,000 रुपये तक बढ़ सकती है। यहा से फिर से मजबूत खरीदारी की संभावना है। दूसरी ओर एएनजेड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड की वरिष्ठ कमोडिटी रणनीतिकार डैनियल हाइन्स को संदेह है।

माइक्रोवेव में पिघला बर्तन, पति-पत्नी को आया आइडिया, खड़ा कर दिया करोड़ों का कारोबार

नई दिल्ली एजेंसी। मधुमिता उदय कुमार और जगदीश कुमार चेन्नई से हैं। पति-पत्नी की इस जोड़ी ने एक सफल कारोबार खड़ा कर दिया है। उनके स्टार्टअप का नाम 'द इंडस वैली' है। इसकी नींव दोनों ने साल 2016 में डाली थी। इसका आइडिया उन्हें एक निजी हादसे के बाद आया था। तब माइक्रोवेव में एक प्लास्टिक का बर्तन पिघल गया था। इसने उन्हें हेल्दी कुकवेयर के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। इसका मकसद भारतीय रसोई को रसायनों से मुक्त करने के साथ खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक रूप में वापस लाना है। आज यह ब्रांड रसायनों से मुक्त कुकवेयर का विकल्प दे रहा है। कुछ ही सालों में इस बिजनेस का वैल्यूएशन करोड़ों में पहुंच गया है। आइए, यहां मधुमिता और जगदीश की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। मधुमिता उदय कुमार और जगदीश कुमार चेन्नई के रहने वाले हैं। साल 2016 में उन्होंने अपने स्टार्टअप 'द इंडस वैली' की शुरुआत की थी। इसका विचार एक घरेलू दुर्घटना के बाद आया, जब माइक्रोवेव में प्लास्टिक का बर्तन पिघल गया। मधुमिता ने महसूस किया कि हम रेसिपी और सामग्री पर तो ध्यान देते हैं। लेकिन, जिस बर्तन में खाना बन रहा है, उसकी सेहत को नजरअंदाज करते हैं। बाजार में भरोसेमंद और पारंपरिक विकल्पों (जैसे मिट्टी, लोहा, पीतल के बर्तनों) की कमी को देखकर मियां-बीवी ने इस कमी को पूरा करने का फैसला किया। व्यावसायिक मोर्चे पर कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी का रेवेन्यू 61 प्रतिशत बढ़कर 117 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 72.5 करोड़ रुपये था। मुख्य रूप से कुकवेयर उत्पादों की बिक्री से 114.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई। हालांकि, विज्ञापन और परिचालन खर्चों में बढ़ोतरी हुई। लेकिन, कंपनी ने अपनी वित्तीय दक्षता में सुधार किया है। कपल ने दिसंबर 2024 में 23 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई थी। इसके कंपनी का वैल्यूएशन अब बढ़कर 303 करोड़ रुपये हो गया है।

राधाकिशन दमानी, डॉली खन्ना, मुकुल अग्रवाल ने मार्च तिमाही में नई कंपनियों में लगाया पैसा

मुंबई, एजेंसी। मार्च क्वार्टर में घरेलू शेयर बाजारों की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस दौरान निफ्टी में 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। एक तरफ जहां छोटे निवेशक इस पीरियड में परेशान दिखे तो वहीं दिग्गज निवेशकों ने कई कंपनियों में पैसा लगाया। राधाकिशन दामानी से लेकर मुकुल अग्रवाल तक शेयर बाजार के चर्चित सुपरस्टार्स ने मार्च तिमाही में अनेकों कंपनियों में इनवेस्टमेंट किया है। आइए जानते हैं कि वो कंपनियां कौन सी हैं दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी ने दांव लगाया है। यह स्टॉक इस साल 12 प्रतिशत तक लुढ़क चुका है। वहीं, बीते एक साल में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 39 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। मार्च तिमाही के दौरान मुकुल अग्रवाल का फोकस एनर्जी सेक्टर की कंपनियों पर टिका रहा। उन्होंने टू कलर में 1.62 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। यह कंपनी डिजिटल टेक्साटाइल प्रीटिंग सेगमेंट में काम करती करती है। मौजूदा समय में यह स्टॉक अपने इश्यू प्राइस से भी नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। बता दें, आज सोमवार को टू कलर के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर बीएसई में 179 रुपये के स्तर पर खुले थे।

अमेरिका-ईरान सीजफायर अधर में लटका

नई दिल्ली, एजेंसी। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर टिकी हुई थी। लेकिन, पाकिस्तान में 21 घंटे की मैराथन बातचीत के बावजूद यह समझौता नहीं हो पाया। इसने दो हफ्ते के लिए लागू सीजफायर के भविष्य को अब अधर में लटका दिया है। दोनों पक्ष वार्ता विफल होने के लिए एक-दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। इस बीच भारत ने अपने बंदोबस्त बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ईंधन सप्लाई में आई बाधाओं के बीच भारत ने ताबड़तोड़ कदम उठाए हैं। उसने छोटे पांच किलो के एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बढ़ा दी है। इसी के साथ पाइप से मुहैया कराई जाने वाली नैचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन का विस्तार भी तेज कर दिया है। यही नहीं, घरेलू एलपीजी उत्पादन को बढ़ाकर 60 फीसदी करने में भी कामयाबी हासिल की है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 23 मार्च से अब तक पांच किलो के 13 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडर बेचे गए हैं। इनकी दैनिक बिक्री एक लाख से अधिक हो गई है। यह कदम प्रवासी श्रमिकों और कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इसी अवधि में 4.24 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं, 30,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन वापस कर पीएनजी को अपनाया है। हालांकि, कच्चे तेल की कमी को अन्य स्रोतों से पूरा कर लिया गया है। लेकिन, एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी है। होटल-रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई में कटौती की है।

संकट से पहले फरवरी में जहां रोजाना लगभग 77,000 सिलेंडर बिक रहे थे। वहीं, पिछले दो-तीन सप्ताह में यह संख्या एक लाख से अधिक हो गई है। सरकार के अनुसार, घरेलू एलपीजी सप्लाई कुल मिलाकर स्थिर बनी हुई है। कहीं भी कमी की सूचना नहीं है। 11 अप्रैल को 52 लाख से अधिक सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मांग का लगभग 98 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पूरा हो रहा है। वहीं, वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 93 फीसदी लेनदेन में सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता भी अब संकट से पहले के स्तर के करीब 70 फीसदी तक बहाल हो गई है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकारों के साथ मिलकर सप्लाई को सुचारु बना रही हैं। सरकार के मुताबिक, रिफाइनरियां ऊंची क्षमता पर काम कर रही हैं। कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। साथ ही, घरेलू एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है। भारत अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को बढ़ाने में भी सफल रहा है। इससे देश की कुल जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो रहा है।

ऐसे समय में जब आयातित ईंधन की सप्लाई पर दबाव बना हुआ है।

आईपीओ की आहट, 12 प्रतिशत चढ़ा टाटा ग्रुप का स्टॉक, निवेशकों में खरीदने की होड़

मुंबई, एजेंसी। एक तरफ शेयर बाजार में आज सोमवार को भारी बिकवाली देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी टाटा केमिकल्स और टाटा इनवेस्टमेंट के शेयरों को खरीदने की होड़ सी मची हुई है। इस उछाल के पीछे की वजह टाटा संस की लिस्टिंग की संभावना को माना जा रहा है। बता दें, 2024 के बाद टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में एक दिन में अबतक यह सबसे बड़ी तेजी है। वहीं, यह लगातार चौथा कारोबारी दिन है जब टाटा केमिकल्स के शेयरों में उछाल दर्ज की गई है। टाटा केमिकल्स के शेयर आज सोमवार को बीएसई में 688.10 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 12 प्रतिशत की तेजी के बाद 773.10 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। बता दें, बीते 8 में से 6 कारोबारी दिनों में टाटा केमिकल्स के शेयरों का भाव ऊपर ही चढ़ा है। इस दौरान टाटा की इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 32 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

टाटा इनवेस्टमेंट के शेयरों की कीमतों में 8.5 प्रतिशत की तेजी आज सोमवार को देखने को मिली है। टाटा इनवेस्टमेंट का शेयर 650.45 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 722.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गए। टाटा इनवेस्टमेंट की भी टाटा संस में हिस्सेदारी है। आरबीआई के अपर लेयर एनबीएफसी नियमों में अगर कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। तब की स्थिति में मौजूदा नियमों के अनुसार टाटा संस की लिस्टिंग अनिवार्य हो जाएगी। अगर टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग होती है तो यह मौजूदा निवेशकों के लिए काफी अच्छी खबर होगी। टाटा केमिकल्स के 2025 के रिपोर्ट के अनुसार टाटा संस में कंपनी की कुल होल्डिंग्स 10237 सिक्योरिटीज है। तब उसकी कीमत 57 करोड़ रुपये थी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)